

तरुण छत्तीसगढ़

आम आदमी का अपना दैनिक अखबार

E-mail: tarunpressraipur@gmail.com
tarun_press@yahoo.co.in
Web: www.tarunchhattisgarh.in
facebook.TarunChhattisgarh
phone: 0771-2543112

■ रायपुर,रविवार 29 नवंबर 2026 ■ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष-4 ■ वर्ष -42 ■ अंक-239 ■ पृष्ठ 8 ■ डाक संस्करण 30 नवंबर 2026 ■ मूल्य-2.00 रुपये

रायपुर से नागपुर कत्लखाना ले जा रहे 16 मवेशियों से भरा आयशर वाहन पकड़ा

भिलाई नगर 29 नवंबर रायपुर की ओर से आयशर वाहन में मवेशियों को भरकर नागपुर कत्लखाने ले जाने की सूचना पर थाना कुम्हारी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। पुलिस टीम ने साईं मंदिर के पास घेराबंदी कर वाहन क्रमांक KA 07 V 3345 को रोककर जांच की।वाहन में 12 गाय एवं 04 बछड़ों सहित कुल 16 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर अमानवीय तरीके से परिवहन करते पाया गया। मवेशियों के परिवहन के संबंध में चालक एवं परिचालक कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 16 मवेशी एवं आयशर वाहन सहित कुल 3,90,000 रुपये की संपत्ति जप्त की। थाना कुम्हारी पुलिस द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए रायपुर की ओर से नागपुर कत्लखाने ले जाए जा रहे 16 मवेशियों से भरे आयशर वाहन को पकड़ा गया। मौके से वाहन चालक एवं परिचालक को गिरफ्तार कर मवेशियों तथा परिवहन में प्रयुक्त वाहन को जप्त किया गया। थाना कुम्हारी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि रायपुर की ओर से एक आयशर वाहन क्रमांक KA 07 V 3345 में मवेशियों को भरकर नागपुर स्थित कत्लखाने ले जाया जा रहा है। सूचना पर थाना कुम्हारी पुलिस टीम द्वारा तत्काल साईं मंदिर के पास घेराबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोका गया। वाहन की जांच करने पर उसमें 12 नग गाय, 03 नग काले बछड़े एवं 01 नग अन्य बछड़ा सहित कुल 16 मवेशी ठूंस-ठूंसकर एवं अमानवीय तरीके से भरे हुए पाए गए। मवेशियों के परिवहन के संबंध में चालक एवं परिचालक कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस द्वारा वाहन चालक अकबर पाशा एवं परिचालक तबरेज पाशा को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध थाना कुम्हारी में अपराध क्रमांक 389/2026 के तहत छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 6, 10, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(1) एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 66/192 के तहत वैधानिक कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

'संचार साथी' से 14 लाख से अधिक खोए मोबाइल फोन बरामद

नई दिल्ली, 29 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 140वें एपिसोड में डिजिटल सुरक्षा से जुड़े सरकारी प्लेटफॉर्म 'संचार साथी' की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस प्लेटफॉर्म की मदद से देशभर में अब तक 14 लाख से अधिक खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए जा चुके हैं।

, पीएम मोदी ने 'मन की बात' में दी जानकारी

प्रधानमंत्री ने कहा कि मोबाइल फोन खोना केवल एक उपकरण खोना नहीं है, बल्कि उसमें मौजूद यादें, जरूरी दस्तावेज और जानकारियां भी खो जाती हैं। ऐसे में 'संचार साथी' लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है। अब तक इसके पोर्टल पर 30 करोड़ से अधिक बार विजिट किया जा चुका है, जबकि करीब तीन करोड़ बार इसका ऐप डाउनलोड हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक



मोबाइल फोन की एक विशिष्ट पहचान होती है, जिसे आईएमईआई नंबर कहते हैं। मोबाइल गुम होने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के साथ 'संचार साथी' पोर्टल पर आईएमईआई नंबर और जरूरी जानकारी देकर फोन ब्लॉक कराया जा सकता है। इसके बाद कोई दूसरा सिम डालकर फोन का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो पुलिस को उसकी पहचान करने में मदद मिलती है।

फ्रॉड नंबरों की जानकारी देने की अपील-पीएम मोदी ने लोगों से संदिग्ध कॉल और धोखाधड़ी वाले मोबाइल नंबरों की जानकारी भी पोर्टल पर साझा करने की अपील की। उन्होंने पुणे के हिमांशु का उदाहरण दिया, जिन्होंने 300 से अधिक संदिग्ध नंबरों की शिकायत की। उनके प्रयासों से करीब 18 हजार मोबाइल कनेक्शन रद्द कराने में मदद मिली। इसी तरह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर निवासी विवेक ने 900 से अधिक फ्रॉड नंबर साझा किए, जिससे करीब 17 हजार कनेक्शन बंद कराने में मदद मिली। प्रधानमंत्री ने बताया कि बैंक, भुगतान ऐप, दूरसंचार कंपनियों और पुलिस सहित 1600 से अधिक संस्थान इस व्यवस्था से जुड़े हैं। इसकी मदद से पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक के संभावित नुकसान को रोका गया है। उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म 23 भाषाओं में उपलब्ध है और इसका इस्तेमाल आसान है। लोगों की छोटी-छोटी सावधानियां डिजिटल दुनिया को अधिक सुरक्षित बना सकती हैं।

सड़क हादसे में एक ही परिवार के 13 लोगों की मौत, 4 बच्चे भी शामिल

रामगढ़,29 नवंबर। झारखंड के रामगढ़ जिले में रविवार देर रात भीषण सड़क हादसे ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं। कुजू ओपी क्षेत्र के NH-33 रांची-पटना मुख्य मार्ग पर पैंकी गांव के समीप स्कॉर्पियो और अज्ञात वाहन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिहार के नालंदा जिले के बेन थाना क्षेत्र के जंघारो गांव का एक परिवार स्कॉर्पियो (BR 21P 6331) से झारखंड के प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर में पूजा-अर्चना करने आ रहा था। वाहन में कुल 14 लोग सवार थे। इसी दौरान पैंकी गांव के पास स्कॉर्पियो आगे चल रहे एक अज्ञात वाहन से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोगों को गंभीर चोटें आईं।इस हादसे में चार महिलाओं, पांच पुरुषों और चार मासूम बच्चों समेत कुल 13 लोगों की जान चली गई। वहीं, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घायल को रामगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्य विवेक कुमार की पत्नी को सरकारी शिक्षक की नौकरी मिलने की खुशी में पूरा परिवार रजरप्पा मंदिर में पूजा-अर्चना करने जा रहा था। विवेक कुमार निजी स्कूल के संचालक बताए जा रहे हैं।जिस परिवार में नई नौकरी मिलने की खुशी में जश्न और पूजा की तैयारी थी, वहां इस हादसे के बाद मातम छा गया।



हादसे की सूचना मिलते ही रामगढ़ के उपायुक्त ऋतुराज, पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत, एसडीपीओ आलोक रंजन समेत प्रशासन और पुलिस के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे।

8 लाख का इनामी नक्सली चंदर समेत 5 गिरफ्तार

कांकेर,29 नवंबर। छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर में माओवादी संगठन को दोबारा स्थापित करने की कोशिश पर पुलिस ने शिकंजा कसा है. कांकेर जिले के जंगल में छिपे पांच नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया. इसमें आठ लाख रुपये का इनामी माओवादी DVCM चंदर कतलाम भी शामिल है. जानकारी के मुताबिक, सभी माओवादी क्षेत्र में ग्रामीणों की बैठक लेकर संगठन को फिर से सक्रिय करने की तैयारी में थे. इसी दौरान पुलिस को इसकी मुखबिरी मिल गई, जिसके बाद मेंड्रा इलाके में कार्रवाई करते हुए पांचों को गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं उनका छठवां साथी मंगेश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. गिरफ्तार किए गए माओवादियों में चंदर कतलाम (DVCM), मंगलू (पड़डा काकानार एरिया कमांडर), मनीषा परचापी, रमशीला और सनकी शामिल हैं. सभी को गोंडाहूर थाना लाया गया है. ये पांचों 28 नवंबर के दोपहर से पुलिस की हिरासत में बताए जा रहे हैं, जबकि फरार मंगेश की तलाश जारी है. सूत्रों के मुताबिक, क्षेत्र में कमजोर पड़ चुके माओवादी नेटवर्क को दोबारा सक्रिय करने के उद्देश्य से ये लोग ग्रामीणों की बैठक आयोजित करने की तैयारी में थे. इसके जरिए ग्रामीणों से संपर्क बढ़ाने और संगठन को फिर से खड़ा करने की योजना बनाई जा रही थी. लेकिन बैठक होने से पहले ही पुलिस को इसकी भनक लग गई. मुखबिरी के आधार पर पुलिस ने मेंड्रा इलाके में कार्रवाई की और पांचों माओवादियों को पकड़ लिया.

इस कार्रवाई में सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी DVCM चंदर कतलाम की मानी जा रही है. चंदर पर आठ लाख रुपये का इनाम घोषित था. वह माओवादी संगठन में डिविजनल कमेटी मेंबर के पद पर बताया जाता है. उसके साथ मंगलू की गिरफ्तारी भी अहम है, जो पड़डा काकानार क्षेत्र का एरिया कमांडर बताया जा रहा है. इन दोनों की गिरफ्तारी से उत्तर बस्तर में माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है. अब बस्तर से माओवादियों का ख़ात्मा हो गया यह माना जा सकता है. इस पूरी कार्रवाई के बीच हथियारों की बरामदगी को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है. सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने एक AK-47 और एक SLR बरामद की है. हालांकि, हथियारों की बरामदगी की आधिकारिक पुष्टि और ये हथियार किसके कब्जे से मिले, इसकी जानकारी सामने आना बाकी है.

इस मामले में एक और गंभीर पहलू सामने आ रहा है. सूत्रों के हवाले से गिरफ्तार माओवादियों के साथ हिरासत में कथित मारपीट किए जाने की बात भी कही जा रही है. हालांकि, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

ट्रांसफर-पोस्टिंग के नाम पर वसूली, दीपक टंडन का साला गिरफ्तार

रायपुर। ब्लैकमेलिंग और वसूली के मामले में दीपक टंडन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके साले कमल प्रसाद चौबे को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में सिंडिकेट से जुड़े लोगों और कथित बॉस के बारे में जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि कथित बॉस का नाम पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ IPS अफसर से जुड़ा है। ट्रांसफर-पोस्टिंग के नाम पर अवैध वसूली किए जाने के आरोप भी जांच में सामने आए हैं। हालांकि पुलिस ने अभी संबंधित अफसर का नाम सार्वजनिक नहीं किया है।

ट्रेलर की टक्कर से स्कूटी सवार युवती की मौत

रायगढ़,29 नवंबर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में आज भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार ट्रैलर ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी. स्कूटी पर सवार युवती उछल सड़क पर जा गिरी. गंभीर चोटें आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. शव उठाने का विरोध करते हुए उन्होंने चक्काजाम कर दिया है. जानकारी के मुताबिक, खरसिया के रानीसागर इलाके में हादसा हुआ है. ट्रैलर की टक्कर से स्कूटी सवार युवती सड़क पर जा गिरी. हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुटने लगी. आक्रोशित होकर उन्होंने सड़क के बीच बाइक रखकर चक्काजाम कर दिया. फिलहाल मृतिका की पहचान नहीं हो पाई है. सूचना मिलने के बाद पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची. उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर चक्काजाम खत्म कराने का प्रयास किया. हालांकि आक्रोशित जनता ने मृतिका के शव को उठाने से मना कर दिया.



बताया जा रहा है कि जिस ट्रैलर ने टक्कर मारी, उसका चालक फरार हो गया. पुलिस किसी तरह स्थानीय ग्रामीणों को समझाइश देकर चक्काजाम खत्म कराने की कोशिश कर रही है. इसके बाद ही शव को पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज जाएगा. मार्ग पर आवागमन बाधित होने से वाहनों के पहिए थम गए हैं.

विधायक की गाड़ी पर पथराव

कोरबा,29 नवंबर। छत्तीसगढ़ में जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। पाली-तानाखार विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम के वाहन पर बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात व्यक्ति ने पत्थर फेंक दिया। पत्थर वाहन के उस हिस्से में लगा, जहां विधायक बैठे हुए थे। हमले से गाड़ी का साइड का कांच टूट गया। राहत की बात यह रही कि विधायक समेत वाहन में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। घटना के बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में नाराजगी है। पार्टी ने देशभर में आंदोलन की चेतावनी देते हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को वाई-प्लस श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है।धार्मिक आयोजन से लौटते समय हुई घटना विधायक तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम शुक्रवार को बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिंघरी पहुंचे थे। यहां आयोजित गौरा-गौरी कार्यक्रम में उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद विधायक अपने वाहन से वापस लौट रहे थे। रात करीब साढ़े 11 बजे सिंघरी के मुख्य मार्ग पर अचानक किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंक दिया। पत्थर की चपेट में आने से वाहन का साइड का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। अचानक हुई इस घटना से वाहन में मौजूद लोग घबरा गए। उस समय विधायक के साथ उनके निजी सुरक्षा अधिकारी सुशील कौशिक और वाहन चालक भी मौजूद थे। चलते वाहन पर अचानक पत्थर लगने के बावजूद चालक ने संयम बनाए रखा। उसने गाड़ी पर नियंत्रण नहीं खोया, जिससे किसी अन्य दुर्घटना की स्थिति नहीं बनी। घटना की जानकारी विधायक के प्रतिनिधि कुलदीप सिंह मरकाम ने दी है। उनके मुताबिक, पथराव के कारण वाहन को नुकसान पहुंचा है, लेकिन विधायक, सुरक्षाकर्मी और चालक में से किसी को चोट नहीं आई है। घटना का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि पत्थर वाहन के उसी हिस्से में लगा, जिस ओर विधायक बैठे हुए थे। इसे लेकर पार्टी पदाधिकारियों ने सुरक्षा संबंधी चिंता व्यक्त की है।



'जहाज तो निकल चुका है', राहुल गांधी को स्टालिन का सीधा जवाब



नई दिल्ली, 29 नवंबर। प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को लेकर कांग्रेस और डीएमके के बीच तकरार बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के वरिष्ठ नेताओं के साथ चेन्नई पहुंचकर डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन से मुलाकात करने वाले हैं। उनका उद्देश्य स्टालिन को प्रस्तावित विधेयक का विरोध करने के लिए मनाना है। हालांकि, स्टालिन ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि डीएमके तमिलनाडु और यहां के लोगों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी। स्टालिन ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर राहुल गांधी का धन्यवाद करते हुए कहा कि संविधान और राज्यों के अधिकारों की रक्षा में डीएमके की ऐतिहासिक भूमिका को स्वीकार करना सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने हमेशा तमिलनाडु और तमिल लोगों के हितों को सर्वोपरि रखा है। इतिहास उन्हें वीरों के रूप में याद रखेगा, गद्दारों के रूप में नहीं। वहीं, डीएमके की ओर से राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा गया, 'जहाज तो निकल चुका है।' पार्टी ने कहा कि उसे राहुल गांधी से काफी उम्मीदें थीं और समर्थन देने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन डीएमके अपने नेता के नेतृत्व में तमिलनाडु के हित में ही फैसला लेगी। दरअसल, विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' परिसीमन के मुद्दे पर सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है। इससे भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपने फायदे के लिए चुनावी नक्शा बदलने का अवसर मिल सकता है। राहुल गांधी ने स्टालिन से देश के हित, तमिलनाडु के अधिकारों और संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होकर विधेयक का विरोध करने की अपील की है। डीएमके पहले भी परिसीमन प्रस्ताव का विरोध कर चुकी है। पार्टी का कहना है कि यदि लोकसभा सीटों का पुनर्वितरण केवल आबादी के आधार पर किया गया, तो दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

स्टालिन और शरद पवार से मिलेंगे खरगे-सोनिया गांधी

परिसीमन बिल का विरोध करने के लिए मनाएंगे, दोनों की पार्टियां बिल के सपोर्ट में

एक बार फिर मोदी सरकार 30 नवंबर को लोकसभा में परिसीमन-महिला आरक्षण बिल पेश करेगी। पिछली बार की अपेक्षा इस बार मोदी सरकार के लिए रास्ता साफ नजर आ रहा है। परिसीमन बिल पास कराने के लिए सरकार की राह आसान होती जा रही है। पिछली बार विरोध करने वाली विपक्षी पार्टियां डीएमके और एनसीपी (शरद पवार) ने बिल का समर्थन करने का ऐलान किया है। विपक्ष की धार कुंद होने के बाद मल्लिकार्जुन खरगे और सोनिया गांधी आज एमके स्टालिन और शरद पवार से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे स्टालिन और शरद पवार से मिलकर उन्हें मनाएंगे। सोनिया गांधी भी स्टालिन और पवार से बातचीत करके बिल का विरोध करने को कहेंगी।

बिजली तार के संपर्क में आई धान से भरी ट्रॉली, देखते ही देखते राख हो गई किसान की खून-पसीने की कमाई

कवर्धा,29 नवंबर। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक किसान की मेहनत की कमाई आग की भेंट चढ़ गई। खेत से धान भरकर घर लौट रहे किसान की ट्रॉली में बिजली की तार के चपेट में आने से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि ट्रॉली में रखा पूरा धान जलकर राख हो गया।

इस हादसे में किसान को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। घटना कवर्धा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बोधाईकुंडा की है। किसान दीपचंद वर्मा अपने खेत से ट्रैक्टर-ट्रॉली में धान भरकर घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में 11 हजार वोल्ट का बिजली तार काफी नीचे की ओर लटक रहा था। जैसे ही धान से भरी ट्रॉली वहां से गुजरी, वह बिजली तार के संपर्क में आ गई। इसके बाद अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और ट्रॉली में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि किसान को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही देर में ट्रॉली में रखा पूरा धान जलकर राख हो गया। आग की वजह से ट्रॉली के चारों पहिए भी जल गए। ट्रॉली में करीब एक एकड़ खेत की धान की फसल रखी हुई थी, जिसे किसान घर लेकर जा रहा था। महीनों की मेहनत के बाद तैयार हुई फसल को घर पहुंचाने से पहले ही आग ने सबकुछ छीन लिया।



दिसंबर में हो सकते हैं नगरीय निकाय चुनाव: साव

रायपुर,29 नवंबर। अंतिम मतदाता सूची का सोमवार को प्रकाशन होगा. इसके साथ ही नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर न केवल राजनीतिक दलों की बल्कि आम लोगों की निगाहें लग जाएंगी. उहापोह की इस घड़ी में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि दिसंबर में नगरीय निकाय चुनाव हो सकते हैं. उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से नगरीय निकाय चुनाव की चर्चा करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग अपनी तैयारी कर रहा है. भाजपा हर चुनाव को गंभीरता से लेती है. सभी 17 नगरीय निकायों में भाजपा की तैयारी है. पिछली नगरीय निकाय का परिणाम दोहराया जाएगा. हमारी सरकार ने 3 सालों में शहरों के लिए काम किया है. शहर की जनता भाजपा को आशीर्वाद देगी. वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस की हालत काफी बुरी है. जिलाध्यक्ष प्रभारी की बैठक में नहीं पहुंच पा रहे हैं. कांग्रेस को अपने जिलाध्यक्षों को नोटिस भेजना पड़ रहा है. कांग्रेस में हालात बुरे हैं.

पीसीसी चीफ दीपक बैज की प्रदर्शन पर तंज-वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज के परफॉर्मेंस पर तंज कसते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हारे-पीटे हुए लोगों की पार्टी बनी हुई है. कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है. कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष अपनी कार्यसमिति नहीं बना पाए. हालांकि, यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है.वहीं कल से शुरू होने संसद सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले परिसीमन बिल पर अरुण साव ने कहा कि लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिल पास हो चुका है. महिला आरक्षण का बिल जल्द लागू होगा. आरक्षण बिल जब पेश हुआ था तब विपक्षी पार्टियों का महिला विरोधी चेहरा उजागर किया था. आरक्षण बिल आएगा, परिसीमन भी होने वाला है. विपक्षी दल आत्मघाती कदम उठा रहे है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा. शराब घोटाला मामले में विकास अग्रवाल की गिरफ्तारी पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जांच में बहुत सी बातें उजागर हो रही हैं. जांच के अनुक्रम में जो भी तथ्य आएंगे उसपर कार्रवाई होगी.



श्रीनगर में पारा शून्य से 2 डिग्री नीचे

श्रीनगर,29 नवंबर। जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में रविवार को न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे बना रहा और यह माइनस 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि, यह पिछले दिन के माइनस 2.4 डिग्री सेल्सियस की तुलना में थोड़ा बेहतर रहा। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रविवार को श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि, यह पिछले दिन के माइनस 2.4 डिग्री सेल्सियस की तुलना में थोड़ा बेहतर रहा। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रविवार को श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि गुलमर्ग में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस और पहलगाम में माइनस 3.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

एक नजर

प्रोटेक्शन प्लान बंद कराने के नाम पर क्रेडिट कार्ड से उड़ाए 1.81 लाख रुपये

भिलाई 29 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। साइबर ठगी अब बैंक अधिकारी बनकर लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं ऐसा ही मामला पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के अकलोरडीह निवासी रविकांत धुरंधर के साथ सामने आया है ठगी ने खुद को एक्सिस बैंक का अधिकारी बताकर उनके क्रेडिट कार्ड से दो अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए कुल एक लाख 81 हजार 998 रुपये निकाल लिए पीड़ित का आरोप है कि साइबर हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी स्थानीय थाने में अब तक एफआइआर दर्ज नहीं की गई है रविकांत धुरंधर, पिता स्वर्गीय खुमान सिंह धुरंधर ने बताया कि उनके मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया उसने खुद को एक्सिस बैंक का अधिकारी बताते हुए कहा कि उनके क्रेडिट कार्ड पर प्रोटेक्शन प्लान सक्रिय है इसे बंद नहीं कराने पर हर महीने 99 रुपये शुल्क कटता रहेगा। प्लान निष्क्रिय करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने की बात कही गई। बैंक अधिकारी की बातों पर भरोसा कर रविकांत ने बताए गए तरीके से प्रक्रिया शुरू की इसी दौरान ठग ने उनके क्रेडिट कार्ड से रकम निकाल ली पीड़ित के अनुसार, 17 नवंबर को चैप्टर मार्केट के नाम पर एक लाख 37 हजार 998 रुपये और एस ट्रेड्स के नाम पर 44 हजार रुपये का ट्रांजेक्शन किया गया इस तरह कुल एक लाख 81 हजार 998 रुपये की ठगी हुई पीड़ित ने साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने के बाद भिलाई-3 थाने में भी आवेदन दिया उनका आरोप है कि पुलिस जांच की बात कहकर उन्हें वापस लौटा रही है और अब तक एफआइआर दर्ज नहीं की गई है।

रूआबांधा में धारदार हथियार लहराकर राहगीरों को धमकाने वाला गिरफ्तार



भिलाई 29 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। राहगीरों को धमकाने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है भिलाई नगर पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर रूआबांधा बस्ती क्षेत्र में सार्वजनिक सड़क पर धारदार हथियार लेकर लहराकर राहगीरों को भयभीत करने की सूचना चौकी रूआबांधा पुलिस को मिली थी मौके पर पहुंची पुलिस ने रूआबांधा बस्ती, बजरंग चौक, चौकी रूआबांधा निवासी अजय कंडरा उर्फपप्पू को पकड़ा गया उसके पास से स्टील का धारदार हथियार जब्त किया है आरोपी के खिलाफआर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया

स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, नेवई में 28.07 करोड़ के निर्माण कार्य प्रारंभ

दुर्ग, 29 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। दुर्ग जिले में स्थित छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, नेवई में आधारभूत संरचना के विस्तार के क्रम में राज्य शासन द्वारा कुल ?28.07 करोड़ की लागत के पाँच निर्माण कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। लोक निर्माण विभाग के कार्यापालन अभियंता श्री ए.के. भट्टाचार्य ने बताया कि इन कार्यों में कुलपति निवास (बी-टाइप) 1 नग, कुल सचिव, कुलाधिसचिव, प्राध्यापक एवं सह-प्राध्यापक निवास (डी-टाइप) 13 नग, सहायक प्राध्यापक निवास (ई-टाइप) 10 नग, वर्कशॉप भवन तथा 250 सीटर बालक छात्रावास का निर्माण शामिल है। उक्त सभी निर्माण कार्यों के कार्यादेश भी जारी कर दिए गए हैं। छात्रावास का निर्माण पूर्ण होने पर संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय परिसर में ही आवास की सुविधा मिलेगी, जिससे दुर्ग जिले सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं देश के अन्य राज्यों से आने वाले विद्यार्थी अपनी तकनीकी शिक्षा पर बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

वार्ड-9 में सड़क डामरीकरण का भूमिपूजन महापौर अलका बाघमार ने किया

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता



दुर्ग 29 नवंबर। नगर पालिक निगम दुर्ग। शहरवासियों को सुगम, सुरक्षित एवं बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा शहर की सड़कों के सुधार एवं अधोसंरचना विकास कार्यों को लगातार गति दी जा रही है। इसी क्रम में वार्ड क्रमांक 9 में 18.24 लाख रुपये की लागत से सड़क डामरीकरण कार्य कराया जाएगा। महापौर अलका बाघमार ने आज गोपाल मंदिर से चंद्राकर ट्रेडर्स, बैगा पारा स्टेडियम के समीप प्रस्तावित सड़क डामरीकरण कार्य का भूमिपूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की।

सड़क डामरीकरण कार्य पूर्ण होने के बाद वार्डवासियों को बेहतर सड़क की सुविधा मिलेगी। इस मार्ग से प्रतिदिन आवाजाही करने वाले हजारों लोगों को राहत मिलेगी। सड़क की खराब स्थिति के कारण होने वाली परेशानियों से निजात मिलने के साथ ही आवागमन अधिक सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित होगा। क्षेत्रवासियों को लंबे समय से बेहतर सड़क की आवश्यकता महसूस हो रही थी, जिसे देखते हुए नगर निगम द्वारा इस कार्य को प्राथमिकता से कराया जा रहा है। भूमिपूजन के पश्चात महापौर अलका बाघमार ने सभापति श्याम शर्मा, लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर, जनप्रतिनिधियों एवं निगम अधिकारियों के साथ निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सड़क निर्माण कार्य की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले स्थल को व्यवस्थित किया जाए तथा डामरीकरण कार्य निर्धारित मापदंडों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए।

महापौर ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। कार्य के दौरान नागरिकों को आवागमन में अनावश्यक परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और सभी कार्य निर्धारित समय में पूर्ण होने चाहिए। महापौर अलका बाघमार ने कहा कि नगर निगम दुर्ग शहर के सभी 60 वार्डों में नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप मूलभूत सुविधाओं एवं विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा कर रहा है। बेहतर सड़क, पेयजल, स्वच्छता एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना निगम की प्राथमिकता है। वार्डों में लगातार विकास कार्यों के माध्यम से शहर को बेहतर और व्यवस्थित बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

बाल अधिकारों,पॉक्सो अधिनियम, साइबर सुरक्षा एवं बाल संरक्षण का शिक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता



दुर्ग, 29 नवंबर । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण , नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार तथा माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ प्रतीम साहू, कार्यकारी अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग श्री के. विनोद कुजूर के निर्देशन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव श्री उमेश कुमार भागवतकर के समन्वय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा संचालित सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत आज शिक्षकों के लिए एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय भवन, दुर्ग के चतुर्थ तल स्थित नवीन कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया।

प्रातः 10:30 बजे से सायं 04:00 बजे तक आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को बाल अधिकारों, बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों, यौन शोषण की पहचान, साइबर अपराधों से सुरक्षा तथा बच्चों को समय पर विधिक एवं संस्थागत सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में प्रशिक्षित एवं जागरूक करना था।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के अध्यक्ष श्री के. विनोद कुजूर, कुटुम्ब न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश श्रीमती सुमन एक्का एवं प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शेख अशरफ उपस्थित रहे। कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारियों, संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों, विभिन्न विद्यालयों से आए शिक्षकों तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चयनित ग्रामों में कार्यरत सामुदायिक मध्यस्थों की विशेष सहभागिता रही।

कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से स्वागत उद्बोधन एवं कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बाल संरक्षण के क्षेत्र में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री के. विनोद कुजूर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ने अपने मुख्य वक्तव्य में कहा कि बच्चों की सुरक्षा केवल परिवार अथवा प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि विद्यालय और शिक्षक भी इस दायित्व के महत्वपूर्ण सहभागी हैं। शिक्षक बच्चों के व्यवहार, परिस्थितियों एवं भावनात्मक परिवर्तनों को निकटता से समझते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की प्रताड़ना, शोषण अथवा असुरक्षा की स्थिति की पहचान कर समय पर उचित कदम उठाने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बाल अधिकारों के संरक्षण को सामाजिक एवं संस्थागत प्राथमिकता बनाने पर बल दिया।

प्रशिक्षण सत्र में श्री अवध किशोर, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), दुर्ग द्वारा बाल अधिकारों एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के विभिन्न प्रावधानों, अपराधों एवं दंडात्मक व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बच्चों के विरुद्ध होने वाले लैंगिक अपराधों की पहचान तथा कानून के अंतर्गत उपलब्ध संरक्षणात्मक प्रावधानों के संबंध में शिक्षकों को जागरूक किया।

कई लोगों को पावर आफ अटार्नी देकर धोखाधड़ी करने के आरोप में युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता



भिलाई 29 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। ग्राम-अरसी की एक ही जमीन के अलग अलग ऋण पुस्तिका तैयार कर कई लोगों को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को बोरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है बोरी टीआई दिलेश्वर चंद्रवंशी ने बताया कि प्रार्थी ने थाना बोरी में लिखित शिकायत दर्ज कराया कि ग्राम अरसी स्थित खसरा नंबर 1051 एवं 1086, प्रत्येक का रकबा 0.16 हेक्टेयर, कुल 0.32 हेक्टेयर भूमि का सौदा आरोपी के साथ 3,00,000 रुपये में तय हुआ था। उक्त राशि प्रार्थी ने ऑनलाइन, बैंक खाते एवं नगद माध्यम से आरोपी को दी गई थी आरोपी दस्तावेजों में त्रुटि होने की बात कहकर उन्हें सुधारने एवं रजिस्ट्री कराने का आश्वासन दिया गया इस दौरान आरोपी ने प्रार्थी को पावर ऑफ अटॉर्नी प्रदान की, जिसके माध्यम से प्रार्थी स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्री करा सकता था। लगभग 11 माह बाद प्रार्थी को जानकारी मिली कि आरोपी ने उसी भूमि के संबंध में अन्य व्यक्ति के नाम पर भी पावर ऑफ अटॉर्नी देकर रजिस्ट्री करा दी है। तहसील कार्यालय से जानकारी लेने पर उक्त भूमि के नामांतरण संबंधी प्रक्रिया में कई व्यक्तियों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया जाना सामने आया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बोरी में धारा 318 (4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया विवेचना के दौरान आरोपी के फरार होने पर थाना बोरी थाने पुलिस लगातार तलाश की। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर संभावित ठिकानों पर तलाश एवं दबिश दी। पुलिस टीम के प्रयासों से आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ एवं अपराध में संलिप्तता के आधार पर आरोपी दीपक देशलहरे (36 साल) निवासी ग्राम अरसी, थाना बोरी को गिरफ्तार किया है

नगर निगम रिसाली क्षेत्र में वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य शीघ्र होगा प्रारम्भ

दुर्ग 29 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। जिले के नगर निगम रिसाली क्षेत्र में वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट हेतु 134 करोड़ राशि की घोषणा मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा विगत दिवस रिसाली के वार्ड 18 में आयोजित कार्यक्रम में की गई है। मुख्यमंत्री के घोषणा को अमल में लाने प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष दुर्ग ग्रामीण विधायक श्री ललित चंद्राकर और कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने नगर निगम रिसाली, जल संसाधन और पीएचई के अधिकारियों के साथ आज चिन्हांकित स्थल का निरीक्षण किये। उन्होंने अधिकारियों को अलग-अलग कम्पोनेंट वार एस्टीमेट बनाने के साथ नगर की भविष्य को ध्यान में रखते हुए योजना बनाने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि नगर निगम रिसाली अपने प्रस्तावित कार्ययोजना के तहत नेवई उमरपोटी सीमा में स्थित डेम से पानी लेकर प्लांट स्थापित करेगा। आगामी 30 वर्ष को लेकर योजना तैयार की गई है।

ग्राम सांकरा में बूथ क्रमांक-70 पर मन की बात का 140वां एपिसोड सुना गया



■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

उतई 29 नवंबर। ग्राम सांकरा सरपंच कार्यालय स्थित बूथ क्रमांक 70 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 140वें एपिसोड को सामूहिक रूप से सुना गया। इस अवसर पर भाजयुमो मंडल अध्यक्ष एवं सरपंच रवि सिंगौर ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशवासियों को प्रेरणा देने के साथ-साथ समाज में सकारात्मक बदलाव और जनसेवा की भावना को मजबूत करता है। कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे प्रेरणादायक कार्यों और जनहित के विषयों पर अपने विचार साझा करते हैं। कार्यक्रम में छोटू यादव बूथ अध्यक्ष, महेंद्र पारधी पंच, शुभम जांगड़े पंच, सांसद प्रतिनिधि मनहरण सिंगौर, पिंटू यादव, प्रशिक्षण प्रमुख एवं सोशल मीडिया प्रभारी कामता सिंगौर, नारायण चंद्राकर, वरुण सिंगौर, बल प्रमुख हुमान दास सहित अन्य ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

बिना वैध दस्तावेज के मवेशी परिवहन करते दो आरोपी पकड़े गए, 3.90 लाख रुपये के मवेशी जब्त



■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

भिलाई 29 नवंबर। कटलखाना ले जाते हुए वाहन को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा गया है। जिसमें 16 मवेशियों को दूस-दूसकर भरा गया था मवेशियों की कीमत 3.90 लाख रुपए है कुम्हारी मवेशियों की कीमत 3.90 लाख रुपये, घेराबंदी कर वाहन को पकड़ा गया कुम्हारी प्रभारी पारस ठाकुर ने बताया कि साई मंदिर के पास घेराबंदी कर वाहन केए 07 वी 3345 को रोककर जांच करने पर वाहन में 12 गाय, 04 बछड़ों समेत 16 मवेशी बरामद किए गए मवेशियों के परिवहन को लेकर चालक काकिया मोहल्ला? कास, कोलार, कर्नाटक निवासी अकबर पाशा, बीडी कॉलोनी, कास, जिला कोलार, कर्नाटक तबरेज पाशा को पकड़ा गया। दोनों के पास किसी भी प्रकार का वैद्य दस्तावेज नहीं था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेरबंदी किया था। वाहन रायपुर की ओर से मवेशियों को भरकर नागपुर स्थित कत्लखाने लेकर जा रही थी पुलिस टीम साई मंदिर के पास घेराबंदी कर पकड़ा है आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 6, 10, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 (1) एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 66/192 के तहत जुर्म दर्ज किया है

महिलाओं से लूट की दो वारदातों में शामिल एक युवक और दो अपचारी बालक गिरफ्तार

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता



भिलाई 29 नवंबर। हिलाओं के साथ लूट की दो घटनाओं का दुर्ग पुलिस ने खुलासा किया है सीसीटीवी फुटेज एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर एक आरोपी एवं दो अपचारी बालक को दुर्ग सिटी कोतवाली थाने गिरफ्तार किया गया है उनके पास से लूटी गई नगदी रकम, मोबाइल, आधार कार्ड बरामद किया गया है दुर्ग सिटी कोतवाली टीआई नवीन राजपूत ने बताया कि दिगंबर जैन मंदिर के पास स्कूटी सवार तीन व्यक्तियों ने महिला का पर्स लूट लिया था। वहीं आरोपियों ने शनिचरी बाजार से सब्जी बेचकर घर लौट रही महिला से भी बिक्री की रकम 6000 रुपए लूट लिए थे 26 नवंबर को महिला दिगंबर जैन मंदिर के पास जा रही थी तभी स्कूटी सवार तीन अज्ञात व्यक्तियों ने उसका पर्स लूट लिया था पर्स में वनप्लस कंपनी का मोबाइल फोन, नगदी रकम एवं आधार कार्ड रखा हुआ था इसी तरह दूसरी घटना में शनिचरी बाजार से सब्जी बेचकर घर लौट रही महिला को तीन व्यक्तियों द्वारा निशाना बनाकर उससे 6000 रुपए की लूट की गई थी। दोनों ही घटनाओं की रिपोर्ट पर पुलिस जांच में जुटी हुई थी।

अब थाना-चौकी में क्यूआर कोड स्कैन कर देख सकेंगे ई-चालान, ऑनलाइन भुगतान की सुविधा आसान

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता



भिलाई 29 नवंबर। अब ई-चालान देखने और भुगतान करने के लिए इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं वाहन चालक अपने नजदीकी थाना अथवा चौकी पहुंचकर वहां लगाए गए क्यूआर कोड स्टिकर को अपने मोबाइल से स्कैन कर सीधे ई-चालान की आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंच सकेंगे। इसके माध्यम से वे अपने वाहन का लंबित चालान देख सकेंगे तथा ऑनलाइन भुगतान भी कर सकेंगे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) कौशलेन्द्र देव पटेल ने बताया कि इस क्यूआर कोड स्टिकर में ई-चालान देखने एवं भुगतान करने की पूरी प्रक्रिया को चित्रों और विवरण के साथ 10 सरल चरणों में प्रदर्शित किया गया है। इसमें गूगल कैमरा अथवा गूगल लैंस से क्यूआर कोड स्कैन करने, आधिकारिक वेबसाइट खोलने, पे चालान विकल्प चुनने, वाहन नंबर एवं कैप्चा दर्ज करने, चालान का विवरण देखने तथा यूपीआई सहित अन्य ऑनलाइन माध्यमों से भुगतान करने की जानकारी दी है भुगतान पूर्ण होने के पश्चात रसीद डाउनलोड एवं प्रिंट करने की प्रक्रिया भी समझाई गई है स्टिकर में क्यूआर कोड के साथ परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट भी अंकित की है ताकि नागरिक क्यूआर कोड स्कैन करने के अतिरिक्त वेबसाइट का नाम स्वयं दर्ज कर भी ई-चालान की जानकारी प्राप्त कर सकें साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से नागरिकों से अपील है कि ई-चालान भुगतान के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें। किसी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक न करें

सामान्य ट्राइसाइकिल मिलने से शिव प्रसाद के लिए आना-जाना हुआ आसान

दुर्ग, 29 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंदों के जीवन में किस तरह नई उम्मीद और खुशियां लेकर आती हैं, इसका एक प्रेरणादायक उदाहरण रिसाली निवासी श्री शिव प्रसाद कुर्रे हैं। शारीरिक बाधता के कारण उनके लिए स्वयं चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाना बेहद कठिन था। बिना ट्राईसाइकिल के उनका कहीं आना-जाना लगभग असंभव था। दैनिक जीवन के छोटे-छोटे कार्यों के लिए भी उन्हें दूसरों की सहायता का इंतजार करना पड़ता था। इस परेशानी से निजात पाने और आत्मनिर्भर बनने की उम्मीद के साथ श्री शिव प्रसाद कुर्रे ने समाज कल्याण विभाग में ट्राईसाइकिल प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। समाज कल्याण विभाग द्वारा उनके आवेदन पर संवेदनशीलता के साथ विचार एवं आवश्यक परीक्षण के पश्चात आवेदन स्वीकृत किया गया। विगत दिनों रिसाली नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 18 स्थित दुर्गा मंच में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के हाथों श्री शिव प्रसाद कुर्रे को सामान्य ट्राईसाइकिल प्रदान की गई। सामान्य ट्राईसाइकिल प्राप्त होना शिव प्रसाद कुर्रे के लिए महज एक उपकरण मिलना नहीं, बल्कि अपने जीवन को नई दिशा देने जैसा है। अब उन्हें हर छोटी-बड़ी दूरी तय करने के लिए दूसरों की मदद का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वे अपनी सुविधानुसार आवागमन कर सकेंगे और दैनिक जीवन के कार्यों में पहले से अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

संक्षिप्त समाचार

डॉ. दिनेश उपाध्याय का सम्मान

सिमगा,29 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़)। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय औरेठी में व्याख्याता डॉ. दिनेश कुमार उपाध्याय के शासकीय सेवा के 25 वर्ष एवं जीवन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर विद्यालय परिवार की ओर से न्योता-भोज एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा जगत, जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न संस्थाओं से जुड़े अतिथियों ने शामिल होकर उन्हें शुभकामनाएं दीं।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विकासखण्ड शिक्षा



अधिकारी संजय श्रीवास्तव एवं संभव स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के जनरल मैनेजर एम. गोपी कृष्ण मूर्ति रहे। वहीं इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ सुनील मिश्रा, अधिवक्ता परीक्षित चतुर्वेदी, वंदना पब्लिक स्कूल सिमगा के संचालक शिवधारी देवांगन, आईटीआई सिमगा के संस्था प्रमुख मोहन लाल देवांगन, सत्यव्रत मिश्रा, दिव्या तम्बोली, नीता शर्मा, मंजू शुक्ला, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अजय उपाध्याय, साधना यादगार एवं आशीष शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे।इस अवसर पर डॉ. उपाध्याय के 25 वर्षों के शैक्षणिक सेवाकाल, अनुभव और समर्पण की सराहना करते हुए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सिमगा, लांजा, बिनेका, तुलसी एवं झिरिया के शिक्षक-शिक्षिकाओं की भी सहभागिता रही।कार्यक्रम का आयोजन शाला प्रबंधन समिति एवं विद्यालय परिवार के सहयोग से किया गया। अंत में प्राचार्य रामशंकर वर्मा ने सभी अतिथियों, शिक्षकों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

जिला पंचायत सीईओ ने कसडोल में की ग्रामीण विकास योजनाओं की गहन समीक्षा

बलौदाबाजार-भाटापारा,29 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़)। सीईओ जिला पंचायत सुश्री दिव्या ने आज जनपद पंचायत कसडोल में चायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, तकनीकी सहायक की बैठक लेकर ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा की। ग्राम पंचायतवार कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए रोजगार की मांग के अनुरूप कार्य उपलब्ध रखने एवं क्रियान्वयन में तेजी लाने पर जोर



दिया गया।जिला पंचायत सीईओ ने संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को आपसी समन्वय से लंबित कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने तथा योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुँचाने के निर्देश दिए।बैठक में वीबी -जीरामजी अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में मांग के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने तथा चिन्हित विशिष्ट कार्यों को जनवरी माह से पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। ग्राम पंचायतवार कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए रोजगार की मांग के अनुरूप कार्य उपलब्ध रखने एवं क्रियान्वयन में तेजी लाने पर जोर दिया गया।प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों की पूर्णता, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत शत-प्रतिशत बैंक लिंकेज तथा स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत अपूर्ण शौचालयों एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों की प्रगति की भी गहन समीक्षा की गई।बैठक में समस्त ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, तकनीकी सहायक तथा जनपद पंचायत के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने पूर्व महाधिवक्ता कनक तिवारी को दी श्रद्धांजलि

रायपुर, ,29 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़)।छत्तीसगढ़ के पूर्व महाधिवक्ता एवं वरिष्ठ विधिवेत्ता श्री कनक तिवारी के निधन पर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शनिवार को दुर्ग स्थित मुक्तिधाम पहुंचकर दिवंगत वरिष्ठ अधिवक्ता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिवार



के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि श्री कनक तिवारी का निधन छत्तीसगढ़ के विधिक एवं बौद्धिक जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि विधि, साहित्य और वैचारिक चिंतन के क्षेत्र में श्री तिवारी का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। शिक्षा मंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने इस दुःख की घड़ी में शोकाकुल परिजनों को धैर्य और संबल प्रदान करने की कामना की।

चीक समाज की समृद्ध परंपराओं और सामाजिक उत्थान के प्रयासों को सरकार का पूरा सहयोग : मुख्यमंत्री

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता



रायपुर 29 नवंबर.मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि चीक समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपरागत कौशल और सामाजिक एकजुटता छत्तीसगढ़ की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वस्त्र निर्माण की अपनी प्राचीन परंपरा के माध्यम से इस समाज ने सदियों से जनजीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाज की समस्याओं के समाधान और उसके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। मुख्यमंत्री श्री साय आज जशपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड अंतर्गत ग्राम जोकरी में आयोजित प्रांतीय चीक-चिक जाति उत्थान समिति के सामाजिक सम्मेलन एवं सांस्कृतिक महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम पंचायत बनकोम्बो में चीक समाज के सामाजिक भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपये तथा ग्राम जोकरी में महतारी सदन निर्माण के लिए 30 लाख रुपये देने की घोषणा की। सम्मेलन में विभिन्न प्रांतों से आए समाज के पदाधिकारियों, सामाजिक प्रमुखों एवं हजारों की संख्या में समाज के सदस्यों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि चीक समाज ने अपनी मेहनत, कौशल और परंपरागत व्यवसाय के माध्यम से समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राचीन काल से ही समाज द्वारा निर्मित वस्त्रों का उपयोग होता आया है। यह परंपरागत हुनर समाज की विशिष्ट पहचान और गौरवशाली विरासत है। उन्होंने सम्मेलन में बड़ी संख्या में उपस्थित समाज के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में समाज के लोगों का एकजुट होकर अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए आगे आना प्रसन्नता की बात है। ऐसे आयोजन सामाजिक एकता को मजबूत करने के साथ नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आगामी 13 दिसंबर को प्रदेश सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इन तीन वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों को पूरा करने और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचाने की दिशा में निरंतर कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए संचालित महतारी वंदन योजना प्रदेश की लाखों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 33 किस्तों के माध्यम से 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की जा चुकी है। प्रतिमाह मिलने वाली एक हजार रुपये की सहायता राशि से महिलाओं को अपनी छोटी-बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निराकरण के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 प्रारंभ की गई है। इस व्यवस्था से 8 हजार से अधिक अधिकारियों को जोड़ा गया है, ताकि नागरिकों की शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना से जरूरतमंद परिवारों का घर का सपना हो रहा पूरा : मुख्यमंत्री साय

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर 28 नवंबर. मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज जशपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड अंतर्गत ग्राम जोकरी में प्रधानमंत्री आवास योजना की हितग्राही श्रीमती मंजू भगत के नवनिर्मित पक्के आवास का फीता काटकर गृह प्रवेश कराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने परिवार के सदस्यों से आत्मीय मुलाकात की और उनके नए घर की खुशियों में सहभागी बने।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हर जरूरतमंद परिवार का अपना पक्का घर हो, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि किसी परिवार के लिए अपना घर केवल चारदीवारी और छत नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य का आधार होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से ऐसे लाखों परिवारों के सपने साकार हो रहे हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि जब किसी



जरूरतमंद परिवार को अपना पक्का घर मिलता है और परिवार की महिला उस घर की मालकिन बनती है, तो यह खुशी और भी बढ़ जाती है। यह महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।श्रीमती मंजू भगत के परिवार के लिए यह अवसर विशेष खुशी का रहा। वर्षों से संजोया अपना पक्का घर होने का सपना पूरा होने पर परिवार के सदस्यों में उत्साह दिखाई दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रीमती मंजू भगत एवं उनके परिजनों को नए आवास की बधाई देते हुए कामना की कि उनका यह घर सदैव सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे।उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री साय ग्राम जोकरी में आयोजित प्रांतीय चीक-चिक जाति उत्थान समिति के सामाजिक सम्मेलन एवं सांस्कृतिक महोत्सव में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की हितग्राही के घर पहुंचकर गृह प्रवेश कराया।

लोकभवन में मनाया गया विभिन्न राज्यों का स्थापना दिवस

रायपुर, 29 नवम्बर.राज्यपाल श्री रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में आज लोकभवन में 7 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि यह आयोजन केवल राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस मनाने का अवसर नहीं, बल्कि उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, गौरवशाली इतिहास, परंपराओं और विकास यात्रा को जानने-समझने तथा आपस में जुड़ने का माध्यम है। यह आयोजन हमारी विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने और राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ करने का संदेश देता है। राज्यपाल ने कहा कि हमारी भाषाएं, संस्कृतियां, परंपराएं और भौगोलिक विशेषताएं भले ही अलग-अलग हों, लेकिन हमारी राष्ट्रीय पहचान एक है। उन्होंने देश की रियासतों को एकजुट कर अखंड भारत के निर्माण में सरदार वल्लभभाई पटेल के ऐतिहासिक योगदान का स्मरण किया। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री स्व अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शी सोच से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ के बारे में लोग सोचते थे कि यह नक्सली राज्य है और यहां शांति नहीं है। लेकिन अब प्रदेश की पहचान बदल चुकी है। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद का प्रभाव समाप्त हो गया है.

प्रशासन व पुलिस का अपराधियों मे भय और जनता में विश्वास हो : कलेक्टर

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

बलौदाबाजार 29 नवम्बर.जिले मे बेहतर क़ानून व्यवस्था बनाए रखने एवं आगामी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर कुलदीप शर्मा एवं एसपी गौरव राय ने शनिवार को पुलिस एवं राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर क़ानून व्यवस्था क़ी समीक्षा क़ी। बैठक मे सुदृढ़ क़ानून व्यवस्था के लिये राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों क़ी बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि क़ानून व्यस्था बनाए सभी सतर्कता से काम करें, सूचना तंत्र मजबूत रखें। नियमों एवं क़ानून का सख़्ती से पालन कराएं ताकि प्रशासन के प्रति अपराधियों मे भय और जनता मे विश्वास हो। उन्होंने कहा कि जमीन अतिक्रमण, आपसी विवाद, अवैध परिवहन,यातायात नियम,अवैध शराब पर कड़ी नजर रखी जाए और नियमनुसार



समय पर कार्यवाही होनी चाहिए। बांड ओवर और बांड डाउन क़ी अधिक से अधिक कार्यवाही किया जाए। बैठक मे जिला बदर होने वाले अपराधियों पर विशेष निगरानी रखने तथा अवैध शराब निर्माण व विक्रय पर कड़ी कार्यवाही पर जोर दिया गया। अवैध शराब के विरुद्ध आबकारी और पुलिस क़ी टीम द्वारा लगातार जांच व निरीक्षण किया जाएगा। शराब दुकान मे नियुक्त होने वाले सेल्स मेन क़ी पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराने के निर्देश जिला आबकारी अधिकारी को दिया गया ताकि आपराधिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति सेल्स मेन के कार्य मे संलग्न न रहे। इसके साथ ही शराब दुकान के सुपरवाइजर द्वारा थाने मे कैश जमा कराने जाने के लिये पुलिस क़ी पेट्रोलिंग टीम साथ रहेगी ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। सोशल मीडया के बढ़ते उपयोग और प्रभाव पर चर्चा करते हुए भड़काऊ और भ्रामक सामग्री पोस्ट पर कार्यवाही के लिये मीडिया मॉनिटरिंग सेल एवं सायबर सेल द्वारा कड़ी निगरानी क़ी जाएगी। इसके साथ ही लोगों को सोशल मीडिया पोस्ट एवं आईटी एक्ट के बारे मे जागरूक करने क़ी बात कही गई। इसी तरह यातायात नियमों के उल्लंघन पर ई - चालान कटने पर सम्बंधित को जुमने क़ी राशि जमा कराने क़ी प्रक्रिया के लिये कार्ययोजना तैयार करने कहा गया। एनएच किनारे के होटल व ढाबों का निरीक्षण राजस्व एवं पुलिस द्वारा सतत निरीक्षण करने के निर्देश दिये गए। इस दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारी भी साथ होंगे। खाद्य पदार्थों का विधिक सैम्पल लिया जाएगा।

तीन दुकानों में चोरी का खुलासा, एक गिरफ्तार

शटर और ताले तोड़कर नगदी व सामान चुराने की वारदातों में नाबालिग भी शामिल, 2 हजार रुपए बरामद

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता



बलौदाबाजार, 29 नवंबर। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में दुकानों के शटर और ताले तोड़कर चोरी करने की तीन वारदातों का सिटी कोतवाली पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके साथ शामिल विधि से संघर्षरत एक बालक को अभिरक्षा में लिया गया है। आरोपी की निशानदेही पर चोरी की रकम में से 2 हजार रुपए भी बरामद किए गए हैं।पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में संपत्ति संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस ने मंडी रोड स्थित लक्की सेल कपड़ा बाजार, पुराने बस स्टैंड की माईजी किराना दुकान और सदर बाजार रोड स्थित राजा कपड़ा बाजार में हुई चोरी की घटनाओं की जांच की।पहली घटना में 6 नवंबर की रात लक्की सेल कपड़ा बाजार का शटर उठाकर गल्ले से नगदी और कपड़े चोरी किए गए थे। दूसरी वारदात 21 नवंबर की रात माईजी किराना दुकान का ताला तोड़कर हुई, जहां से गल्ले में रखी नगदी पार कर दी गई। वहीं, 23 नवंबर की रात राजा कपड़ा बाजार का शटर तोड़कर गल्ले से नगदी चोरी की गई थी।तीनों मामलों में पुलिस ने बीएनएस की धारा 331(4) और 305 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर संदेही दुर्गेश मानिकपुरी उर्फ बरहा (22) को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में उसने अपने नाबालिग साथी के साथ मिलकर सूनी दुकानों के शटर और ताले तोड़कर चोरी करना स्वीकार किया।पुलिस ने आरोपी को 28 नवंबर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। वहीं, विधि से संघर्षरत बालक को किशोर न्याय बोर्ड, बलौदाबाजार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का महाभियान

अब तक 5.35 लाख मीट्रिक टन से अधिक खरीदी, प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक 3,100 रुपये में विक्रय

रायपुर, 29 नवंबर ,29 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़)। छत्तीसगढ़ में चल रहे धान खरीदी महाभियान के तहत 27 नवंबर तक 5 लाख 34 हजार 798 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। अब तक प्रदेश के 1 लाख 33 हजार 404 किसानों ने सुगमता से अपना धान बेचा है। वहीं, 27 नवंबर को एक ही दिन में 90 हजार 910 टन धान की खरीदी दर्ज की गई है। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य पारदर्शी और सुचारू रूप से जारी है। 27 नवंबर को एक ही दिन में 90 हजार 910 टन धान की खरीदी की गई।

21 क्विंटल से कम बेचने पर भी मिलेगा पूरे अंतर का लाभ

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने चालू खरीफ सीजन के लिए किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब यदि कोई किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान बेचता है, तब भी उसे कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत पूरे 21 क्विंटल के अंतर की राशि का लाभ मिलेगा। इस निर्णय से खासकर छोटे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और उनमें उत्साह का माहौल है। प्रदेश में किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है।

2,634 केंद्रों में आवक शुरू, टोकन तुंहर हाथ ऐप से मिल रही सुविधा

किसानों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष 360 नए धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। वर्तमान में 2,634 धान उपार्जन केंद्रों में धान की आवक शुरू हो चुकी है। चालू खरीफ सीजन के लिए 28 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। किसान घर बैठे टोकन तुंहर हाथ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर धान विक्रय की तिथि तय कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी केंद्रों में शुद्ध पेयजल, बैठने और प्राथमिक उपचार की समुचित व्यवस्था की गई है।

किसानों की मेहनत का सम्मान सरकार की प्राथमिकता: मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि किसानों की मेहनत का पूरा सम्मान करना और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खरीदी के दौरान किसानों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए और उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाएं निर्बाध रूप से संचालित होती रहें। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि धान खरीदी के दौरान किसानों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए तथा उपार्जन केंद्रों में सभी व्यवस्थाएं सुचारू बनी रहें। राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और किसान हितैषी बनाया गया है।

चैतन्य संस्था के मार्गदर्शन में अमाली और भूमका में निकली नशामुक्ति जागरूकता रैली, ग्रामीणों ने लिया आदर्श ग्राम बनाने का संकल्प

नशा छोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो के नारों से गूंजे गांव, स्वस्थ एवं खुशहाल समाज निर्माण का दिया संदेश

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

नगरी। ग्राम अमाली एवं भूमका में चैतन्य संस्था के मार्गदर्शन में नशामुक्ति जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली के माध्यम से ग्रामीणों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशामुक्त जीवन अपनाने, स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने और अपने गांव को नशामुक्त एवं आदर्श ग्राम बनाने का संदेश दिया गया। इस दौरान ग्रामवासियों ने सामूहिक रूप से गांव को नशामुक्त बनाने तथा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लिया।रैली में महिला स्व-सहायता समूह बिहान की दीदियों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, स्कूली बच्चों, पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान 'नशा छोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो', 'नशे को कहो ना, खुशियों को कहो हां' जैसे प्रेरक नारों से पूरा गांव गूंज उठा। रैली के माध्यम से लोगों को शराब, तंबाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहने और परिवार तथा समाज को स्वस्थ रखने के लिए जागरूक किया गया।ग्राम भूमका में आयोजित रैली में सरपंच, पंचगण, बेलरगांव संकुल अध्यक्ष योगेश्वरी साहू, भोजेश्वरी, राजेश्वरी सहित बिहान की दीदियों एवं ग्रामवासियों का विशेष सहयोग रहा। वहीं स्कूल शिक्षक सुनील साहू ने भी कार्यक्रम में महत्वपूर्ण



सहभागिता निभाई। चैतन्य संस्था की नगरी ब्लॉक समन्वयक भूपेश्वरी साहू उपस्थित रहीं।इसी तरह ग्राम अमाली में सरपंच हिरोंदी बाई ध्रुव, जीआरसी सचिव जमुना साहू, फुलेश्वरी, मथुरा, पंचगण, बिहान की दीदियों एवं ग्रामीणों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। माध्यमिक एवं प्राथमिक शाला अमाली की प्रधानपाठक हर्षलता साहू सहित विद्यालय के समस्त शिक्षक-स्टाफ एवं स्कूली बच्चे भी रैली में शामिल हुए।कार्यक्रम में नगरी थाना प्रभारी गणेश राम कुर्रे एवं पुलिस विभाग के स्टाफ की उपस्थिति भी रही। पुलिस विभाग ने नशे से दूर रहने और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया।इस आयोजन ने ग्रामीणों को यह संदेश दिया कि नशामुक्त समाज का निर्माण केवल किसी एक व्यक्ति या संस्था की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे गांव के सामूहिक प्रयास से ही संभव है। ग्रामीणों ने नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान को निरंतर जारी रखने और अमाली एवं भूमका को स्वस्थ, स्वच्छ, नशामुक्त एवं आदर्श ग्राम बनाने की दिशा में मिलकर काम करने का संकल्प दोहराया।

पंजाब में भाजपा-अकाली गठबंधन,समझदारी का परिणाम

राजनीतिक दलों के गठबंधन राजनीतिक समझदारी का परिणाम होती है। जब दो दलों को यह समझ आता है कि हम अकेले चुनाव जीत नहीं सकते हैं,अकेले चुनाव लड़ने का मतलब है चुनाव हारना और राजनीतिक रूप से नुकसान तो जो गठबंधन होता है वह लंबे समय तक चलता है।यह फायदे का गठबंधन होता है,इसमें दोनों राजनीतिक दलों को फायदा होता है यानी दोनों साथ चुनाव लड़ते हैं तो राज्य में उनकी ताकत बढ़ती है और उनके सत्ता में आने का संभावना बढ़ती है।दोनों राजनीतिक दलों के बीच बड़े छोटे का कोई टकराव नहीं होता है, दोनों अपनी राजनीतिक ताकत को बखूबी जानते हैं,जो छोटा वह खुद को राज्य में छोटा मान लेता है और एक खुद को छोटा मान लेता है तो दूसरे को खुद को बड़ा बताने की जरूरत नहीं रहती है।

पंजाब के भाजपा व शिरोमणि अकाली दल के बीच फिर से एक बार गठबंधन हो गया है तो यह इसी बात का संकेत है कि दोनों को ६ साल बाद सही यह बात समझ आ गई है कि दोनों अकेले पंजाब में ताकत नहीं बन सकते,चुनाव जीत नहीं सकते,सरकार नहीं बना सकते। दोनों के बीच सीटों को लेकर भी कोई मतभेद नहीं है। कोई तनाव नहीं है, कोई इगो की समस्या नहीं है।भाजपा ने खुद को छोटा भाई मान लिया है और शिरोमणि अकाली दल को बड़ा भाई मान लिया है और यह घोषणा तक कर दी है कि गठबंधन चुनाव जीतता है तो सीएम शिरोमणि अकाली दल का होगा।वहीं कांग्रेस में यह राजनीतिक समझदारी यूपी कांग्रेस को दिखानी थी लेकिन कांग्रेस ने भाजपा की तरह राजनीतिक समझदारी नहीं दिखाई उसी का परिणाम है तो सीटों को लेकर सपा व कांग्रेस के बीच विवाद शुरू हो गया है।कांग्रेस ने बिहार में भी ऐसी समझदारी नहीं दिखाई थी और परिणाम बिहार चुनाव में कांग्रेस वाला गठबंधन चुनाव हारा था। भाजपा और अकाली दल के अकाली दल के साथ आने से दोनों को फायदा यह है कि भाजपा को जहां पंजाब की स्थानीय सामाजिक संरचना में अधिक व्यापक पहुंच मिल सकती है। दूसरी ओर अकाली दल के लिए यह गठबंधन राजनीतिक पुनर्जीवन का मौका है। यह सच है कभी पंजाब की राजनीति की निर्णायक शक्ति रहे अकाली दल का जनाधार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से कमजोर हुआ है।पंजाब की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का छह वर्ष बाद फिर साथ आना केवल दो राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन की वापसी नहीं है, बल्कि यह पंजाब के बदलते राजनीतिक समीकरणों का संकेत है, इससे पंजाब के राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। यह गठबंधन 2027 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार के सामने एक मजबूत चुनौती पेश करेगा ही साथ ही विपक्ष कांग्रेस की जीत की संभावना भी कम करेगा। पंजाब में अब मुकाबला पहले की तुलना में अधिक रोचक, प्रतिस्पर्धी और त्रिकोणीय होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतकर पंजाब में सरकार बनाई थी। दूसरी ओर अकाली दल तीन और भाजपा केवल दो सीटों तक सिमट गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा व अकाली दल अलग-अलग चुनाव लड़े थे। कांग्रेस ने सात, आम आदमी पार्टी ने तीन और अकाली दल ने एक सीट जीती, जबकि भाजपा एक भी सीट नहीं जीत सकी। हालांकि भाजपा का मत प्रतिशत करीब 18.6 प्रतिशत रहा और अकाली दल को भी लगभग 13.5 प्रतिशत वोट मिले। इससे साफ है कि दोनों दलों के पास अलग-अलग पर्याप्त राजनीतिक आधार है, लेकिन अलग-अलग लड़ने पर वह वोट प्रभावी सीटों में परिवर्तित नहीं हो पा रहा है। अब छह वर्ष बाद दोनों दलों ने अपने अनुभवों से सबक लेते हुए फिर साथ आने का फैसला किया है। इसे राजनीतिक भूल-सुधार भी कहा जा सकता है और बदली परिस्थितियों की व्यावहारिक स्वीकृति भी।भाजपा देश की सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी है। कांग्रेस की तुलना में उसको अपनी राजनीतिक शक्ति का ज्यादा अहंकार होना चाहिए लेकिन भाजपा में राजनीतिक शक्ति या बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का अहंकार दिखाई दूसरे दलों के साथ गठबंधन करते हुए दिखाई नहीं देता है खासकर वहां जहां पर वह कमजोर है,अकेल चुनाव नहीं जीत सकती। ऐसे राज्यों में वह गठबंधन के साथियों का सम्मान करती है,यही वजह है कि वह उन राज्यों में भी राजनीतिक ताकत बन गई है जहां माना जाता था कि वह अपनी बहुमत की सरकार नहीं बना सकती, साझा सरकार नहीं बना सकती, साझा सरकार बन जाए तो वह बखूबी उसे चलाती भी है।पश्चिम बंगाल और दिल्ली में वह आज एक प्रमुख राजनीतिक ताकत है तो वह राजनीतिक समझदारी के कारण है।कांग्रेस को भाजपा से सीखना चाहिए कि राजनीतिक समझदारी से दूसरे दलों के साथ काम करते हुए किसी राज्य में राजीनीतिक ताकत कैसे बना जा सकता है।

विश्लेषण

रोहिंग्या जनसंहार : अंतर्राष्ट्रीय अदालत का ऐतिहासिक फ़ैसला

तनवीर जाफ़री



रोहिंग्या मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के उन लोगों को कहा जाता है जोकि विगत सैकड़ों वर्षों से म्यांमार, जिसे पूर्व में बर्मा कहा जाता था,के पश्चिमी तटीय प्रांत रखाइन में रहते आ रहे हैं। परन्तु बौद्ध बाहुल्य म्यांमार सरकार इन्हें अपना मूल नागरिक नहीं मानती तथा इन्हें बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी या बंगाली के रूप में चिन्हित करती है। वैसे तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही रखाइन के स्थानीय बौद्धों और रोहिंग्या मुसलमानों के बीच अविश्वास रहा है। 1962 में सैन्य शासन आने के बाद से सरकार और कट्टरपंथी समूहों द्वारा इनके विरुद्ध भेदभाव और दमन और भी बढ़ता गया। 1982 में म्यांमार की सैन्य सरकार ने एक नया नागरिकता क़ानून पारित किया, जिसमें देश के 135 आधिकारिक जातीय समूहों की सूची से रोहिंग्या समुदाय को बाहर कर दिया गया। इससे लाखों रोहिंग्या रातों रात 'राज्यविहीन' हो गए और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार तथा आने-जाने के अधिकार छीन लिए गए। बौद्ध समुदाय द्वारा इसी रोहिंग्या समुदाय के ख़िलाफ़ पहले भी कई दशकों से रुक-रुक कर हिंसा होती रही है। ख़ासकर 1978, 1991-92 और 2012 में भी इनके विरुद्ध जबरदस्त हिंसा हुई थी । परन्तु हिंसा का सबसे भयावह दौर 2016 और 2017 में उस समय आया जबकि अक्टूबर 2016 में 'अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी' नामक एक रोहिंग्या विद्रोही समूह ने सीमा चौकियों पर हमला किया, जिसके जवाब में म्यांमार की सेना ने रखाइन में रोहिंग्या समुदाय के विरुद्ध एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर किया। 'अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी' द्वारा 25 अगस्त 2017 को रखाइन की पुलिस चौकियों पर किये गये एक और हमले के बाद, म्यांमार की सेना और स्थानीय मिलिशिया ने उत्तरी रखाइन में 'क्लियरेंस ऑपरेशन' शुरू किया। इस दौरान रोहिंग्या समुदाय के सैकड़ों गांवों को जला दिया गया, उनकी सामूहिक हत्याएं की गयीं और बड़े पैमाने पर यौन हिंसा की गई, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने "जातीय सफ़ाये का सटीक उदाहरण" बताया और बाद में अंतर्राष्ट्रीय अदालत, आईसीजे ने भी इसे "नरसंहार" ही क़रार दिया। म्यांमार के रखाइन राज्य में लगभग 6 लाख रोहिंग्या अभी भी बचे हुए हैं, जिनमें से क़रीब 1.4 लाख लोग बेहद ख़राब हालात वाले आंतरिक विस्थापन शिविरों में रहने को मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय जांचों के अनुसार, अगस्त 2017 के बाद के शुरुआती महीनों में ही कम से कम 9,000 से लेकर 10,000 से भी अधिक रोहिंग्या मारे गए, जिनमें बड़ी संख्या में छोटे बच्चे भी शामिल थे। कुछ स्वतंत्र मानवाधिकार संगठनों का अनुमान है कि वास्तविक संख्या इससे भी कहीं अधिक हो सकती है। उसके बाद अगस्त 2017 के बाद कुछ ही सप्ताह में 7 लाख से अधिक रोहिंग्या जान बचाकर म्यांमार से भागने को मजबूर हुए। इससे पहले के वर्षों में भागे लोगों को मिलाकर कुल 10 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या विस्थापित हो चुके हैं। सबसे अधिक लगभग 10 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश के सीमावर्ती जिले कॉक्स बाजार के कुटुपालोंग शिविर में रहते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर माना जाता है। जबकि हजारों लोगों को बंगाल की खाड़ी के 'भासन चार' द्वीप पर भी बसाया गया है। इसी तरह मलेशिया दक्षिण-पूर्व एशिया में बांग्लादेश के बाद यह सबसे बड़ा रोहिंग्या शरणार्थी केंद्र है, जहाँ 1 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के पास पंजीकृत रूप में रह रहे हैं।



भारत में भी अनुमानित 40,000 के आसपास रोहिंग्या शरणार्थी जम्मू, हैदराबाद, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान जैसे विभिन्न स्थानों में रह रहे हैं। इनमें से लगभग आधे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के पास पंजीकृत हैं। भारत सरकार इन्हें 'अवैध प्रवासी' मानती है, इसलिए इन पर हर समय पुलिस कार्रवाई, गिरफ़्तारी और वापस भेजे जाने का डर बना रहता है। रिफ़्यूजी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार सैकड़ों रोहिंग्या,जिनमें महिलाएँ और बच्चे भी शामिल हैं,जम्मू , दिल्ली और असम के डिटेंशन सेंटरों या 'होल्डिंग कैंपों' में बंद हैं। हजारों रोहिंग्या समुद्र के रास्ते नावों के माध्यम से थाईलैंड,इंडोनेशिया और इंडोनेशिया के आचे प्रांत में भी पहुँचे हैं। इसके अलावा सऊदी अरब, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में भी दशकों पहले पलायन कर चुके रोहिंग्या समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। गत 19 नवंबर को रोहिंगिया नरसंहार को लेकर पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दायर एक मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 9-6 के बहुमत से इतिहास में पहली बार ऐसा फ़ैसला सुनाया गया जिसमें किसी पूरे देश को नरसंहार के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार मानते हुये दोषी ठहराया गया है। अदालत ने पाया कि 2017 में रखाइन राज्य में म्यांमार के सुरक्षा बलों द्वारा किए गए सैन्य अभियानों का उद्देश्य रोहिंग्या आबादी के एक बड़े हिस्से को ख़त्म करना था। इसमें बड़े पैमाने पर लगभग 10,000 लोगों की हत्याएं ,यौन हिंसा, और बच्चों की हत्या जैसे जघन्य कृत्य शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह भी माना कि म्यांमार, 1948 के 'नरसंहार कन्वेंशन' के तहत इस अपराध को रोकने, इसके लिए क़ानून बनाने और दोषियों को सज़ा देने में विफल रहा है। अदालत ने म्यांमार को आदेश दिया है कि वह विस्थापित रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक घर वापसी सुनिश्चित करे, उनकी संपत्ति लौटाए और पीड़ितों को उचित मुआवज़ा दे।

अदालत द्वारा म्यांमार को संदिग्ध अपराधियों के ख़िलाफ़ तत्काल जांच कर मुक़दमा चलाने और अगले 2 वर्षों के भीतर उठाए गए क़दमों की रिपोर्ट अदालत में पेश करने का निर्देश भी दिया गया है। ह्यूमन राइट्स वाच और क़ानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह फ़ैसला भविष्य के अन्य मामलों के लिए एक बड़ी मिसाल साबित होगा । विशेष रूप से, इसका सीधा असर आईसीजे में लंबित दक्षिण अफ्रीका बनाम इज़रायल/ग़ज़ा विवाद जैसे अन्य नरसंहार मामलों की सुनवाई और क़ानूनी व्याख्या पर भी पड़ सकता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास अपने फ़ैसले को लागू कराने के लिए अपनी कोई पुलिस या सेना नहीं है, लेकिन यह फ़ैसला क़ानूनी रूप से बाध्यकारी है। और यदि म्यांमार इस फ़ैसले का पालन नहीं करता है, तो मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जा सकता है, जिससे म्यांमार की सैन्य सरकार पर वैश्विक प्रतिबंध और कूटनीतिक अलगाव बढ़ सकता है। इस ऐतिहासिक फ़ैसले के बाद अब बांग्लादेश जहाँ 7 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी हैं, और भारत जैसे पड़ोसी देशों को अब म्यांमार पर शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने का एक मजबूत क़ानूनी आधार भी मिल गया है।

राजनीति

भाजपा को सत्ता से हटाने चले सीटों पर ही उलझे विपक्षी दल

अजय कुमार,

2027 की लड़ाई से पहले विपक्ष दिल्ली की बैठकों में उलझा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भाजपा को हराने का दावा करती हैं, पर उनकी बातचीत का केंद्र जनता, बेरोजगारी या महंगाई नहीं, सीटों की गिनती और राजनीतिक हैसियत बन गई है। जिस गठबंधन को भाजपा



के लिए चुनौती बनना था, वह अभी अपने भीतर भरोसा कायम नहीं कर पा रहा। यह कमजोरी भाजपा के लिए अवसर है। सपा ने कांग्रेस के सामने 26 सीटों का प्रस्ताव रखा है। कांग्रेस की ओर से पहले 181 सीटों की मांग की खबर आई, फिर 130 और 120 सीटों के आसपास की दावेदारी सामने आई। फासला साफ है। अखिलेश का तर्क है कि सीटें जीतने की संभावना के आधार पर मिलनी चाहिए। पर जीत का पैमाना कौन तय करेगा? क्या सपा अपने उम्मीदवारों को भी इसी कसौटी पर परखेगी? कांग्रेस की हालत भी किसी भ्रम में रहने लायक नहीं। 2022 में उसने 399 सीटों पर चुनाव लड़ा, सिर्फ दो जीतीं, उसका वोट प्रतिशत 2.33 रहा और 387 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। ऐसे प्रदर्शन के बाद 120-130 सीटों का दावा आत्ममुग्धता लगता है। मगर 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रदेश की 17 में से छह सीटें जीतीं और 9.46 प्रतिशत वोट पाए। सपा ने 62 में से 37 सीटें जीतकर 33.60 प्रतिशत मत हासिल किए। लोकसभा नतीजे विधानसभा की गारंटी नहीं, लेकिन कांग्रेस शून्य भी नहीं। दोनों दल अपने अनुकूल आंकड़े चुन रहे हैं। सपा की 26 सीटों वाली सूची में रामपुर खास और फर्रेंदा जैसी कांग्रेस की जीती सीटें हैं। मथुरा, खेरागढ़, जगदीशपुर और किदवई नगर वे क्षेत्र हैं जहां कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही थी। बागपत, मोदीनगर, हापुड़, जेवर, स्याना, खुर्जा, खैर, इगलास, मांट, आगरा उत्तर, फतेहपुर सीकरी, बिलग्राम-मल्लावां, गोविंद नगर, नानपारा, गोरखपुर शहर, खजनी, पडरौना, फाजिलनगर, पिंडरा और वाराणसी कैंट भी प्रस्ताव में बताए गए हैं। कई क्षेत्रों में कांग्रेस के हजार-दो हजार वोट सपा के तर्क को बल देते हैं, पर जीत उम्मीदवार, समीकरण, संगठन और वोट हस्तांतरण से तय होगी। अखिलेश की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल यह हो सकती है कि वह गठबंधन को साझेदारी नहीं, अधीनता समझ बैठें। पांच प्रत्याशियों की घोषणा बेहट से उमर अली खान, सहारनपुर से आशु मलिक, कैराना से नाहिद हसन, अमरोहा से महबूब अली और ललितपुर से ज्योति लोधी सीटों पर बातचीत के बीच हुई। यह संगठन की तैयारी हो सकती है, लेकिन सहयोगी को भरोसे में लिए बिना घोषणा दबाव की राजनीति लगती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के दावों के बीच यह कदम और चुभता है। इमरान मसूद का आक्रोश इसी अपमानबोध से निकला है। उनका कहना है कि कांग्रेस भीख नहीं मांग रही और गठबंधन में सीटें दया से नहीं, आपसी सहयोग से तय होती हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कांग्रेस ने सीटें मांगी ही नहीं तो 26 का आंकड़ा थोपने का अधिकार किसने दिया। सपा को समझना होगा कि सहयोगी को सार्वजनिक रूप से छोटा करने की कीमत चुकानी पड़ती है। कांग्रेस भी बताए कि कमजोर संगठन वाली सीटों पर उसका दावा किस आधार पर है। ओमप्रकाश राजभर ने इमरान के बयान पर तंज कसते हुए पूछा कि यदि कांग्रेस भीख नहीं मांग रही तो सीटों पर बातचीत के लिए कमेटी लेकर सपा के पास क्यों गई। सपा सांसद एसपी सिंह पटेल ने भी कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसे 50 सीटें देना भी बड़ी बात होगी। उन्होंने कांग्रेस के संगठन और उम्मीदवारों की क्षमता पर भी सवाल उठाए। ऐसे बयान बताते हैं कि भाजपा से मुकाबले की तैयारी कर रहे दोनों दलों के बीच भरोसे से ज्यादा एक-दूसरे की हैसियत नापने की होड़ लगी है। पांच नामों की सामाजिक बनावट भी संदेश देती है। चार मुस्लिम चेहरे और एक ओबीसी महिला उम्मीदवार के जरिए सपा मुस्लिम प्रतिनिधित्व और पिछड़े वर्ग की भागीदारी का दावा मजबूत करना चाहती है। पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक तभी चलेगा जब गैर-यादव पिछड़ों और दलितों को टिकट, संगठन और सत्ता में हिस्सेदारी मिले। मुस्लिम मतदाता भी सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और सम्मान चाहते हैं। ओवैसी की राजनीति मुस्लिम मतों में विकल्प का सवाल उठाती है, जबकि बसपा दलित मतों पर अपनी पकड़ लौटाने की कोशिश कर सकती है। सपा का गणित इन दोनों चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। 26 नवंबर को संविधान दिवस पर प्रस्तावित पीडीए प्रणपत्र सपा की दूसरी बड़ी परीक्षा है। प्रदेश, 75 जिलों और लखनऊ के लिए अलग दस्तावेज बनाने की तैयारी स्थानीय मुद्दों को जगह देने का अवसर है। महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये पेंशन, स्वरोजगार के लिए दो लाख रुपये सहायता, घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और गरीबों को मुफ्त इलाज जैसे प्रस्ताव चर्चा में हैं। ये संभावित वादे हैं, अंतिम घोषणाएं नहीं। लाभार्थियों की संख्या, सालाना खर्च और धन का स्रोत बताना होगा। डॉक्टर-दवा-बिस्तर के बिना मुफ्त इलाज कागज पर रहेगा। लखनऊ में मुफ्त मेट्रो यात्रा और जाम से राहत का वादा भी तभी सार्थक होगा जब परिवहन और बुनियादी ढांचे की ठोस योजना हो। भाजपा इस खींचतान को बैठे-बिठाए भुनाएगी। वह मुस्लिम उम्मीदवारों की सूची से ध्रुवीकरण कर गैर-यादव पिछड़ों, दलितों और लाभार्थियों में पकड़ मजबूत करेगी। उसे भी बेरोजगारी, महंगाई, किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था पर जवाब देना होगा। विपक्षी बिखराव सवालों को मिटाता नहीं, उनकी आवाज दबाता है। 2017 का अनुभव दोनों दलों के सामने है। गठबंधन के बावजूद भाजपा ने 312 सीटें जीतीं, सपा 47 और कांग्रेस सात पर सिमट गई। वोट अपने आप एक-दूसरे को नहीं मिलते। 2024 का साझा प्रदर्शन उत्साह देता है, पर विधानसभा का मुकाबला अलग होगा। यदि सीटों पर सम्मानजनक समझौता हुआ, साझा उम्मीदवार और बूथ स्तर पर तालमेल बना तो लड़ाई कड़ी हो सकती है। यदि समझौता अपमान और मजबूरी में हुआ तो कार्यकर्ता भीतर से साथ नहीं देंगे। और यदि गठबंधन टूटा तो विपक्षी मतों का बंटवारा भाजपा की राह आसान करेगा। अखिलेश को तय करना है कि उन्हें कांग्रेस की जरूरत है या केवल कांग्रेस के नाम की। कांग्रेस को भी तय करना है कि वह जमीन पर ताकत बनाएगी या आंकड़ों से अपनी कीमत बढ़ाती रहेगी। अखिलेश को यह याद रखना होगा कि 2024 की सफलता में कांग्रेस के वोट और राहुल गांधी की सक्रियता का योगदान था। साझेदार की ताकत स्वीकारना कमजोरी नहीं, चुनावी समझदारी है। भाजपा को हराने के लिए अहंकार छोड़ना, ईमानदार समझौता करना और जनता को जवाब देना होगा। वरना विपक्ष हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ेगा, जबकि कारण आज की सौदेबाजी होगी।

चर्चित मुद्दा

परिसीमन की आड़ में नारी शक्ति की राह में रोड़े बिछाते अखिलेश

संजय सक्सेना,लखनऊ,

महिला आरक्षण और परिसीमन का मुद्दा एक बार फिर संसद की दहलीज पर है और इस बार बिल पास कराने के लिए सरकार की तैयारी पहले से ज्यादा मजबूत दिख रही है। वह इसमें कितनी



कामयाब रहेगी, इसकी तस्वीर तीन दिसंबर तक पूरी तरह साफ हो जाएगी। 27 नवंबर को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक 30 नवंबर को लोकसभा में पेश किए जाने की तैयारी है। अतीत के पन्ने पलटे जाएं तो अप्रैल में सरकार को बिल पास कराने में तगड़ा झटका लगा था। 131वां संविधान संशोधन विधेयक 17 अप्रैल को लोकसभा में 298 के मुकाबले 230 वोटों पर गिर गया था, क्योंकि संशोधन के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं जुट सका। इस बार नया संशोधन विधेयक और परिसीमन (द्वितीय) विधेयक लाया गया है। इनमें हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की लोकसभा सीटें 50 प्रतिशत बढ़ाने के साथ विधानसभाओं का आकार भी उसी अनुपात में बढ़ाने का प्रावधान है। सरकार का दावा है कि 2011 की जनगणना के आधार पर हर राज्य का मौजूदा अनुपात बना रहेगा, यानी किसी राज्य की हिस्सेदारी नहीं घटेगी। फिर भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित कुछ अन्य छोटे-छोटे दल अपनी सियासत बचाने के चक्कर में इस बिल के विरोध में एड़ी-चोटी का जोर लगाए हुए हैं। सपा के इस विरोध से यूपी की राजनीति गरमाई हुई है। सपा प्रमुख के विरोध के चलते उत्तर प्रदेश के लिहाज से यह बदलाव बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक यूपी में सांसदों की संख्या 80 से बढ़कर 120 और विधायकों की संख्या 403 से बढ़कर लगभग 605 हो जाएगी। यानी 40 नए सांसद और करीब 200 नए विधायक। विधानसभा का आंकड़ा अनुमानित है और अंतिम संख्या परिसीमन आयोग तय करेगा। मोटे-मोटे अनुमान के अनुसार, एक तिहाई आरक्षण के हिसाब से यूपी में लोकसभा की 40 और विधानसभा की करीब 200 सीटें महिलाओं के लिए इजाद होंगी। इसी लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी 80 सांसदों से विधेयक का समर्थन करने की अपील की है। मोदी सरकार बिल पास कराने को अड़ी हुई है तो इसके सियासी नतीजे अगले वर्ष होने वाले पांच राज्यों के चुनाव के बाद 2029 के लोकसभा चुनाव से पूरी तरह से दिखाई देंगे। बात विपक्ष की की जाए तो उक्त बिल को लेकर विपक्षी खेमे में एकजुटता अब पहले जैसी नहीं दिख रही। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर विरोध किया है, जबकि डीएमके खुलकर इस बिल का समर्थन कर रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी बराबर प्रतिनिधित्व की बात कर रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट करके केंद्र के फैसले का स्वागत किया। मगर यह समर्थन शर्तों के साथ है। उन्होंने मांग की कि 33 प्रतिशत आरक्षण के भीतर अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था हो। अप्रैल में उन्होंने यही मांग दलित और ओबीसी महिलाओं के लिए उठाई थी। साथ ही उन्होंने परिसीमन में सीटों की सीमा तय करने के दौरान गड़बड़ी की आशंका भी जताई। यानी मायावती का रुख पूरी तरह बिना शर्त समर्थन का नहीं, बल्कि स्वागत और संदेह का मिला-जुला है। बसपा की मौजूदा संसदीय ताकत भी इतनी नहीं कि गणित बदल सके। सपा की स्थिति अलग है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के बाद वह दूसरा सबसे बड़ा दल है और लोकसभा में उसके 37 सांसद हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि 2023 में पास हुआ महिला आरक्षण कानून सरकार को तत्काल लागू करना चाहिए, जबकि परिसीमन विधेयक को वे नकार चुके हैं। उनके शब्दों में, पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, पर जिस जल्दबाजी और तरीके से परिसीमन लाया जा रहा है, उसका वह विरोध करती है। उन्होंने इसे भाजपा की राजनीति की सबसे बड़ी भूल बताया है। सपा सूत्रों के मुताबिक वे इसकी तुलना नोटबंदी से करते हैं। बहरहाल, सपा के विरोध की वजहें क्या हैं? इसका अध्ययन किया जाए तो इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह जनगणना और जाति का सवाल है। अखिलेश का तर्क है कि परिसीमन 2011 के आंकड़ों पर होगा और नई जनगणना नहीं हो रही। उनका कहना है कि जनगणना होगी तो जातिगत गणना की मांग उठेगी। सपा की पूरी राजनीति पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण पर टिकी है। पार्टी का सवाल है कि अगर पिछड़ों की आबादी बहुत बड़ी है, तो उनके भीतर की महिलाओं के लिए अलग हिस्सेदारी तय किए बिना 33 प्रतिशत आरक्षण का फायदा किसे मिलेगा। मायावती की एससी-एसटी महिलाओं के लिए अलग कोटे की मांग भी इसी बहस का हिस्सा है। दूसरी वजह सीमांकन पर अविश्वास है। अखिलेश ने लखनऊ में आरोप लगाया कि भाजपा हार की आशंका से परिसीमन और मतदाता सूची के पुनरीक्षण में कथित गड़बड़ियों के जरिए चुनावी नतीजे प्रभावित करना चाहती है। सपा रणनीतिकार इसे सिर्फ सीटें बढ़ाने की कवायद नहीं मानते, बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय और राज्यों के बीच शक्ति-संतुलन का सवाल बताते हैं। सपा का यह भी तर्क है कि यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह कदम सियासी लाभ के लिए उठाया जा रहा है। तीसरी वजह सियासी गणित है, जो आधिकारिक बयानों से ज्यादा हालात से उभरती है। नई सीटों की सीमाएं तय करने का काम आयोग करेगा। आरक्षित महिला सीटें हर परिसीमन के बाद बदलती रहेंगी, इसलिए मौजूदा सांसदों और विधायकों की परंपरागत सीटें भी हिल सकती हैं। जिस पार्टी का आधार कुछ खास इलाकों में केंद्रित हो, उसके लिए सीमाओं के नए नक्शे में अनिश्चितता ज्यादा है। यह विश्लेषकों का आकलन है, सपा ने इसे आधिकारिक वजह के तौर पर नहीं गिनाया है।

सपा के लिए जोखिम भी कम नहीं। भाजपा इस मुद्दे को महिला विरोधी रुख के तौर पर पेश करने की कोशिश करेगी। सपा इसका जवाब यह कहकर दे रही है कि वह कानून को 2023 के स्वरूप में तुरंत लागू करने के पक्ष में है। पार्टी इसे 2027 के चुनाव में यह सवाल बनाकर उठाना चाहती है कि पहले से पास कानून अब तक लागू क्यों नहीं हुआ। संख्याबल की लड़ाई भी अहम है। कांग्रेस का दावा है कि एनडीए के पास 322 वोट हैं और वह 360 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए विपक्ष को तोड़ना चाहता है। ऐसे में सपा का रुख इस बात का भी इम्तिहान होगा कि विपक्ष कितना एकजुट रह पाता है। जबकि सरकार का पक्ष है कि अनुपात बरकरार रहेगा, सीटें बढ़ेंगी और महिलाओं को 2029 से प्रतिनिधित्व मिलेगा। सपा का पक्ष है कि बिना नई जनगणना और जातीय आंकड़ों के यह कवायद पारदर्शी नहीं। संसद में 30 नवंबर के बाद तय होगा कि दो-तिहाई का आंकड़ा जुटता है या नहीं और सपा का दांव सही बैठता है या भारी पड़ता है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव महिला आरक्षण बिल और परिसीमन पर एक कदम आगे तो दो कदम पीछे जाने वाली सियासत कर रहे हैं।

एक नजर

पहली बार केंद्रीय शिक्ष पात्रता परीक्षा के 25 केंद्र बनाए गए

जगदलपुर, 29 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आगामी 12 और 13 दिसंबर 2026 को आयोजित किए जा रहे, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) के 22 वें संस्करण में पहली बार बस्तर (जगदलपुर) को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी केंद्रों की सूची के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के 05 चयनित जिलों–रायपुर (74), दुर्ग-भिलाई (37), बिलासपुर (31), बस्तर (25) और कोरबा (19)–में कुल 186 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें बस्तर को 25 परीक्षा केंद्र आबंटित किए गए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले छत्तीसगढ़ में इस परीक्षा का आयोजन केवल रायपुर, दुर्ग (भिलाई), बिलासपुर और कोरबा जैसे चार प्रमुख शहरों तक ही सीमित था, जिसके कारण बस्तर संभाग के दूरस्थ अंचलों के अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए रायपुर या अन्य बड़े शहरों की लंबी और खर्चीली यात्रा करनी पड़ती थी। अब जगदलपुर में ही परीक्षा केंद्र बन जाने से युवाओं को इस परेशानी से बड़ी मुक्ति मिलेगी। बस्तर में 25 केंद्र खुलने से स्थानीय युवाओं का समय और धन दोनों बचेगा, जिससे क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए इस राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में शामिल होना कहीं अधिक सुलभ हो जाएगा। सीटीईटी के दो दिनों तक चलने वाली यह परीक्षा ऑफ्लाइन (पेन और पेपर) मोड में दो पालियों में संपन्न होगी, जिसमें प्रथम पाली (सुबह 09:30 से दोपहर 12 बजे तक) में कक्षा 06 से 08 के लिए पेपर-ढ्ढढ्ढ और द्वितीय पाली (दोपहर 02:30 से शाम 05 बजे तक) में कक्षा 1 से 5 के लिए पेपर-ढ्ढ आयोजित किया जाएगा। बस्तर के 25 केंद्रों पर 12 दिसंबर को प्रथम पाली में 6,120 और द्वितीय पाली में 3,625 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, जबकि 13 दिसंबर को प्रथम पाली में 6,120 तथा द्वितीय पाली में 6,097 परीक्षार्थी शामिल होंगे।

संसद का विशेष सत्र मातृशक्ति के सशक्तीकरण एवं लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने का अवसर: किरण देव

जगदजपुर, 29 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने संसद के विशेष सत्र को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम और निराधार अटकलों पर प्रहार करते हुए कहा कि संसद का सत्र बुलाना केंद्र सरकार का संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक दायित्व है। उन्होने कहा कि केवल मीडिया रिपोर्टों और अटकलों के आधार पर सरकार की नीयत पर सवाल उठाना विपक्ष की गैर-जिम्मेदाराना मानसिकता, महिला विरोधी सोच और राज्यों के बढ़ते प्रतिनिधित्व के प्रति उनके विरोध को उजागर करता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने संसद के विशेष सत्र को मातृशक्ति के सशक्तीकरण एवं लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने का ऐतिहासिक और स्वर्णिम अवसर बताते हुए कहा कि 'नारी शक्ति वन्दन अधिनियम' केवल चुनावी नारा नहीं, बल्कि मोदी सरकार की संवैधानिक प्रतिबद्धता है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है। देश की आधी आबादी को 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ 2029 के आगामी लोकसभा चुनावों में ही मिल सके। श्री देव ने कहा कि परिसीमन एक व्यापक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसमें समय लगता है। इसलिए महिलाओं को समय पर उनका अधिकार दिलाने के लिए सरकार ने अप्रैल 2026 में भी संविधान संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक पेश कर सार्थक प्रयास किए थे, किंतु कांग्रेस, सपा, राजद और तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों के अड़ियल रवैए के कारण तब इसे लागू नहीं किया जा सका। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने परिसीमन को लेकर दक्षिणी या छोटे राज्यों के हितों को नुकसान पहुंचने के भ्रम को खारिज करते हुए कहा कि प्रस्तावित आनुपातिक विस्तार मॉडल के तहत सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में समान रूप से 50 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान है। इससे लोकसभा की अधिकतम सीटें 550 से बढ़कर 850 (वर्तमान 543 के अनुपात में लगभग 815) होंगी। इस प्रक्रिया से दक्षिण के पांच राज्यों की सीटें 129 से बढ़कर 195 हो जाएंगी।

कृषि महाविद्यालय में अंतर-क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता



जगदलपुर, 29 नवंबर । कुम्हरावंड स्थित शहीद गुण्डाधुर कृषि महाविद्यालय में रविवार से 'अंतर-क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता 2026' का शुभारंभ हुआ। इस खेल आयोजन में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले 29 शासकीय एवं 11 निजी कृषि महाविद्यालयों के 200 चयनित छात्र-छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं।

इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि बस्तर के पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि महाविद्यालय जगदलपुर के अधिष्ठाता डॉ आरएस नेताम ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि महाविद्यालय साजा (बेमेतरा) के अधिष्ठाता डॉ ललित रामटेके और क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र के सहसंचालक डॉ एके ठाकुर उपस्थित रहे। सीनियर अंडर ऑफिसर प्रदीप बघेल के नेतृत्व में प्रोसेशन निकाला गया, जिसमें विभिन्न टीम मैनेजर्स के नेतृत्व में कुल 5 टीम शामिल हुईं। मुख्य अतिथि द्वारा मशाल जलाने और आकाश में रंग-बिरंगे गुब्बारे छोड़ने के साथ ही प्रतियोगिताओं की औपचारिक शुरुआत की गई।

उक्त प्रतियोगिता के पहले दिन एथलेटिक्स के रोमांचक मुकाबले देखने को मिले, जिसमें ईस्ट जोन के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। बालक 100 मीटर दौड़ में ईस्ट जोन के ओम भगत ने प्रथम, सेंट्रल जोन के मुकेश कुमार ने द्वितीय और साउथ जोन के भावेश कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं बालिका 100 मीटर दौड़ में ईस्ट जोन की संध्या नेताम प्रथम, साउथ जोन की गौरी नेताम द्वितीय और वेस्ट जोन की नंदनी भुवार्य तृतीय स्थान पर रहीं। इसी प्रकार बालक 800 मीटर दौड़ में ईस्ट जोन के हरेश ने पहला, वेस्ट जोन के अरमान ने दूसरा और सेंट्रल जोन के यतीश ने तीसरा स्थान हासिल किया। बालिका 800 मीटर दौड़ में नॉर्थ जोन की कौशलिया प्रथम रहीं, जबकि साउथ जोन की प्रियंका और जीतेश्वरी ने क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही समूह खेलों के अंतर्गत वॉलीबॉल, कबड्डी और खो-खो के क्वार्टर फाइनल मुकाबले भी प्रारंभ हो गए हैं। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी डॉ राम कुमार ठाकुर, डॉ शुभही निषाद, डॉ वीबी कुरवंशी, डॉ जेएल नाग, डॉ अंगद सिंह राजपूत, डॉ सुनील नाग एवं डॉ आरएस नाग सहित विभिन्न अंतर-जोन दल प्रबंधक और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

एनएमडीसी के खिलाफयुवा बेरोजगार संघ के बैनर तले रोजगार के लिए खोला मोर्चा

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता



दंतेवाड़ा, 29 नवंबर। जिले के बचेली एवं किरंदुल परियोजनाओं में एनएमडीसी की एल-1-एल-2 भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा की तारीख घोषित करने की मांग को लेकर शनिवार को स्थानीय युवा बेरोजगार संघ के दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले के सैकड़ो बेरोजगार युवा किरंदुल और बचेली पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एनएमडीसी चेकपोस्ट के पास स्थानीय युवाओं और पुलिस-प्रशासन के बीच जमकर बहस का माहौल बन गया। हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे स्थानीय युवाओं ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से अपील की थी कि, उन्हें पुराने एनएमडीसी चेकपोस्ट तक जाने दिया जाए।

हालांकि, एनएमडीसी के अधिकारियों और प्रशासन की ओर से युवाओं को यह कहकर रोक दिया गया कि अब इसी जगह (नया चेकपोस्ट घोषित कर दिया गया है। आगे जाने से रोके जाने पर नाराज प्रदर्शनकारी उसी चौक पर धरने पर बैठ गए। मौके पर मौजूद एसडीएम और पुलिस अधिकारी प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने की समझाइश देते नजर आए। जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पांच गेट पर बेरिकेड्स लगाए गए हैं, चप्पे-चप्पे पर पुलिस और डीआरजी महिला फाइटर के जवानों को तैनात किया गया है ताकि अप्रिय स्थिति ना बने।

स्थानीय युवा बेरोजगार संघ ने अपनी मांगों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जब तक स्थानीय युवाओं के रोजगार से जुड़े मुद्दों पर ठोस पहल नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा । प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया है कि उनकी मांग स्थानीय युवाओं को रोजगार में उचित अवसर और प्राथमिकता देने की है। उनका कहना है कि वे भीख नहीं मांग रहे, बल्कि अपने ही जिले के संसाधनों से जुड़े रोजगार में अपना जायज हक मांग रहे हैं । युवाओं का कहना है कि एनएमडीसी एक सार्वजनिक क्षेत्र की सरकारी कंपनी है। ऐसे में स्थानीय क्षेत्र के विकास, रोजगार सृजन और प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को अवसर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी उससे अपेक्षित है। रोजगार की मांग उठाना कोई अपराध नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना और अधिकारों के लिए आवाज उठाना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है।

स्थानीय प्रदर्शनकारी रवि नाग का कहना है कि हम भीख नहीं मांग रहे, अपने हक की मांग कर रहे हैं। हमारी धरती के खनिज से देश को लाभ मिल रहा है, तो हमारे जिले के युवाओं को भी रोजगार में उचित अधिकार मिलना चाहिए।

अबूझमाड़ के युवा बस्तर फाइटर्स में भर्ती के लिए बहा रहे पसीना

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता



नारायणपुर, 29 नवंबर। अबूझमाड़ के युवा इन दिनों बस्तर फाइटर्स की भर्ती के लिए नारायणपुर के हाईस्कूल मैदान में पसीना बहा रहे हैं। 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद की समाप्ति के बाद अबूझमाड़ के गांवों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ ही युवा अपने भविष्य को लेकर नए सपने बुन रहे हैं। नारायणपुर पुलिस का 'माड़ परियोर अभियान' युवाओं के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए निःशुल्क शारीरिक और बौद्धिक प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है। नारायणपुर पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार पाटिल ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले के शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाकों के युवाओं को भर्ती प्रक्रिया के लिए बेहतर तरीके से तैयार करना है।

कुतुल से आए युवा अभ्यर्थी उग्रेश कुमार वर्धा ने बताया कि पहले उनके गांव और आसपास के इलाकों में नक्सलियों का प्रभाव था, जिसके कारण युवाओं के मन में भय बना रहता था। लेकिन अब सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के बाद वह बिना किसी डर के पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए नारायणपुर पहुंच पा रहे हैं।उन्होने बताया कि पहले नक्सलियों के दबाव की वजह से डर लगता था। हमें लगता था कि सेना की भर्ती या ट्रेनिंग लेने पर नक्सली हमें मार डालेंगे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, अब तो हम आत्मसमर्पित नक्सलियों के साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगर नक्सली होते तो हम ऐसे ट्रेनिंग लेने नहीं आ पाते। यहां लिखित परीक्षा के लिए भी क्लास लगाई जा रही है। हमें अब यह समझ आ रहा है कि पेपर कैसा होगा। नारायणपुर एसपी संदीप कुमार पाटिल ने बताया कि अभियान के तहत प्रशिक्षण को दो भागों में बांटा गया है। इनडोर प्रशिक्षण में अभ्यर्थियों को सामान्य ज्ञान, जिले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों और लिखित परीक्षा के प्रश्नों को हल करने की तैयारी कराई जा रही है। वहीं आउटडोर प्रशिक्षण में दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक और व्यायाम जैसी शारीरिक गतिविधियों का अभ्यास कराया जा रहा है। एसपी के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य है कि अबूझमाड़ के अधिक से अधिक युवा बस्तर फाइटर भर्ती के लिए आवेदन करें और उन्हें चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की पहले से जानकारी हो। इसके लिए जिले में अलग-अलग स्थानों पर प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं।

जनगणना-2027 की तैयारियां समयबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से करें: कलेक्टर

कांकेर, 29 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने आज जिले के सभी एसडीएम, जनगणना चार्ज अधिकारी, तहसीलदार एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों की बैठक लेकर जनगणना 2027 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जनसंख्या गणना कार्य को सुचारू, व्यवस्थित एवं समयबद्ध ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जनगणना कार्य में एकल शिक्षकीय संस्थाओं के शिक्षकों, गर्भवती महिलाओं एवं दिव्यांगजनों की ड्यूटी नहीं लगाई जाए। मान्यता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थाओं के कर्मचारियों की ड्यूटी भी जनगणना कार्य में लगाई जा सकती है। जनगणना कार्य के लिए ड्यूटी लगाए जाने वाले कर्मचारियों एवं रिजर्व कर्मचारियों का पहले से चिन्हांकन करने के निर्देश दिए गए। सभी तहसीलदार एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों को टीम के प्रत्येक सदस्य का आंकलन कर निर्धारित मापदंड के अनुसार पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने को कहा गया। उन्होंने कहा कि जनगणना कार्य में नियुक्त प्रगणक धैर्यवान एवं जिम्मेदार होना चाहिए।

कांग्रेस ने टेंडर में एआई से बने दस्तावेज फर्जी तरीके से अपलोड करने का लगाया आरोप

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता



कांकेर, 29 नवंबर । नगर पालिका कांकेर में निविदा प्रक्रिया (टेंडर) में कथित फर्जीवाड़े का मामले में करीब 40 लाख रुपये के टेंडर में कूटरचना और फर्जीवाड़े का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने कांकेर कलेक्टर कुंदन कुमार और मुख्य नगर पालिका अधिकारी पवन मेरिया से मुलाकात कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और एफआईआर की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि विभागीय वेबसाइट पर फर्जी तरीके से टेंडर अपलोड किए गए हैं। इस मामले में पहले नगर पालिका अध्यक्ष अरुण कौशिक से भी शिकायत कर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई थी, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है।

कांकेर शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष यासीन कराणी के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने सवाल उठाते हुए कहा कि चेटजीपीटी (एआई) से तैयार किए गए कथित फर्जी टेंडर आखिर विभागीय वेबसाइट पर कैसे अपलोड हो गए? इसके लिए किस आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल किया गया? कांग्रेस नेताओं ने विभागीय वेबसाइट 222.ह्वड्डस्र.प्द्द.द्दश्ा.द्वठ्ठ पर नगर पंचायत नरहरपुर के टेंडर क्रमांक 1033 और नगर पालिका कांकेर के टेंडर क्रमांक 1340 को अपलोड करने वाले व्यक्ति, अपलोड की तारीख और समय की जांच करने की मांग की है।

नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष अजय रेणु ने इस मामले के साथ दो अन्य निविदाओं की भी जांच की मांग उठाई। इनमें कांकेर का टेंडर क्रमांक 1991, जिसकी विक्रय फार्म तिथि 03 मार्च 2026 है और नरहरपुर का टेंडर सूचना क्रमांक 629, जिसकी विक्रय फार्म तिथि 12 मार्च 2026 है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से सुनियोजित तरीके से निविदा प्रक्रिया में कूटरचना की गई है। उन्होंने पूरे मामले में तकनीकी जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी पवन मेरिया ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की ओर से निविदा को लेकर शिकायत दी गई है। संबंधित अवधि में वे अवकाश पर थे, इसलिए उन्हें पूरे मामले की विस्तृत जानकारी नहीं है। फिलहाल दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है और जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

नगर पालिका अध्यक्ष अरुण कौशिक ने कहा कि कांग्रेस पदाधिकारी उनसे भी इस मामले में मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि यह तकनीकी विषय है, इसलिए इसकी वास्तविक स्थिति सीएमओ और तकनीकी अधिकारियों की जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। पूरा कांकेर शहर हम सबका है, विकास कार्यों में कोई भेदभाव नहीं है, सभी जगह फंड बराबर जा रहा है। टेंडर से जुड़े मामले में यदि निविदा प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता पाई जाती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी।

विकासखंड कांकेर में सेभी कराओके गायन प्रतियोगिता की ऑडिशन तिथि तय

कांकेर, 29 नवंबर । अंचल में छुपी प्रतिभा को मंच प्रदान करने के उद्देश्य को लेकर बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के लिए विकासखंड इकाई कांकेर मानस संस्कृति का विस्तार किया गया। जिले के सभी विकासखंडों में गायन विधा पर प्रतियोगिता संपन्न कराने हेतु कार्ययोजना प्रसारित किया गया है, बैठक में सर्वसम्मति से श्री रामायण मंच पंडरीपानी कांकेर मे 13 दिसंबर 2026 को प्रातः 10बजे से ऑडिशन टेस्ट की तिथि तय की गई है तथा उसी दिन मुख्य कार्यक्रम की तिथि निर्धारित की जायेगी, उक्त प्रतियोगिता में 15 वर्ष से अधिक उम्र के कोई भी स्थानीय नागरिक ऑनलाईन पंजीयन कर शामिल हो सकते हैं, ऑनलाईन पंजीयन कराने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर 2026 तक किया गया है, श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान जिला कांकेर से श्री हृदय राम शोरी प्रदेश उपाध्यक्ष, गोवर्धन गजबल्ला प्रदेश सलाहकार, लोकेश साहू प्रांतीय मीडिया प्रभारी के.आर. गजबल्ला जिलाअध्यक्ष, लक्ष्मीकांत साहू मानस संस्कृति जिलासंयोजक, प्रकाश साहू महासचिव, विकासखंड अध्यक्ष भूषण जैन, संरक्षक देवेंद्र यादव, संयोजक दीपक शंकर जैन ,बीरेन्द्र मरकाम, मीडिया प्रभारी बसंत प्रधान,संतोष यादव, ईश्वर मंडावी, प्रद्युम्न श्रीवास, निर्मल तिवारी, प्रवेश चौहान, प्रदीप साहू, मयंक हड़प, यशवंतजैन, नेमेश्वरी साहू एवं मानस संस्कृति परिवार कांकेर के सभी पदाधिकारियों की गरिमा मयी उपस्थिति रही।

भाजपा की विधानसभा स्तरीय बैठक में कार्यकर्ताओं को जनता से जुड़ने पर जोर



■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

जगदलपुर, 29 नवंबर। भारतीय जनता पार्टी संगठन को धार देने और कार्यकर्ताओं को जनता से जुड़कर ज़मीनी स्तर पर कार्य करने में सक्रिय करने के उद्देश्य से लगातार बड़ी बैठकें कर रही है। शनिवार को बस्तर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक बैठक ग्राम मूली में आयोजित हुई। जिसमें कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश लाटिया ,बस्तर विधानसभा प्रभारी श्रीनिवास राव मद्दी, पूर्व विधायक डा. सुभाऊ कश्यप, सह प्रभारी श्रीनिवास मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष वेदप्रकाश पाण्डेय प्रमुखता से शामिल हुए और कार्यकर्ताओं से कमर कसकर बस्तर विधानसभा में भाजपा की जीत का लक्ष्य निर्धारित कर प्राणप्रण से कार्य में जुटने आह्वान किया। बैठक में संगठन को सशक्त बनाने व जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिकाधिक जनता तक कार्यकर्ताओं द्वारा पहुंचाने पर ज़ोर दिया गया।

कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। कार्यकर्ता ही भाजपा की ताकत है। जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ क्षेत्र की जनता को मिले, इसके लिए भाजपा के कार्यकर्ता कर्मठता के साथ जनता से संवाद स्थापित करें, जनता से जुड़े। संगठन को और मजबूत बनाने में योगदान दें।

बस्तर विधानसभा प्रभारी श्रीनिवास राव मद्दी ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं से निरंतर सक्रिय रहने और बस्तर विधानसभा में भाजपा की विजय का लक्ष्य साध कर योजनाबद्ध रूप से कार्य करने कहा। बैठक को भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश लाटिया,पूर्व विधायक डा सुभाऊ कश्यप, भाजपा जिला अध्यक्ष वेदप्रकाश पाण्डेय ने भी संबोधित किया।

बैठक में प्रमुख रूप से जिला उपाध्यक्ष नरसिंह राव, सफीरा साहू, ललिता बघेल, जिला महामंत्री परीस बेसरा, योगेश ठाकुर,संतोष बघेल, विनय सोना, रोहित त्रिवेदी, जनपद अध्यक्ष सोनवारी भद्रे सहित विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, मोर्चा के अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रभारी ,संयोजक-सहसंयोजक, बूथ अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

पहले पखवाड़े में 10 हजार से अधिक किसानों ने बेचा 40 हजार क्विंटल धान



■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

जगदलपुर, 29 नवंबर । खरीफविपणन वर्ष 2026-27 के तहत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। 15 नवंबर 2026 से 27 नवंबर 2026 तक की अवधि में संभाग के कुल 10,007 किसानों से 40,682.32 क्विंटल धान खरीदा जा चुका है। इस वर्ष कुल 2,73,464 किसान पंजीकृत हैं, और 417 धान खरीदी केंद्रों में से अब तक 344 उपार्जन केंद्रों पर खरीदी की शुरुआत हो चुकी है।

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 15,59,040 टन धान उपार्जन का लक्ष्य रखा गया है, जो गत वर्ष (2025-26) के 15,18,521 टन लक्ष्य से अधिक है। ज्ञात हो कि पिछले वर्ष 13,74,383.52 टन धान की खरीदी हुई थी और 2,28,029 किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान विक्रय किया था बस्तर संभाग के अंतर्गत शुरुआती चरण में कोण्डागांव और कांकेर सबसे आगे रहे हैं। कोण्डागांव में 69 केंद्रों के माध्यम से 3,430 किसानों से 17,212.56 क्विंटल धान खरीदा गया, जबकि कांकेर में सभी 163 केंद्रों पर खरीदी शुरू होकर 4,822 किसानों से 16,144.84 क्विंटल धान उपार्जित किया गया है। इसके अलावा बस्तर में 74 केंद्रों पर 1,648 किसानों से 7,040.04 क्विंटल, नारायणपुर में 13 केंद्रों पर 55 किसानों से 151.40 क्विंटल, बीजापुर में 10 केंद्रों पर 36 किसानों से 126.52 क्विंटल, दंतेवाड़ा में 14 केंद्रों पर 15 किसानों से 4.72 क्विंटल और सुकमा में 1 केंद्र पर 1 किसान से 2.24 क्विंटल धान की खरीदी दर्ज की गई है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर की कुल 297 समितियों में से 279 समितियां वर्तमान में धान उपार्जन का कार्य संभाल रही हैं और अन्य केंद्रों पर भी खरीदी प्रक्रिया को गति दी जा रही है।

कृषक उन्नति योजना की किसानों को दें सही जानकारी: कलेक्टर

कांकेर, 29 नवंबर। कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने आज खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, सहकारिता, कृषि विभाग तथा सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, मंडी सचिव, सहकारिता निरीक्षक एवं खाद्य निरीक्षकों की बैठक लेकर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समीक्षा की। उन्होंने धान खरीदी केंद्रों में सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि किसान अपने वास्तविक रकबे में बोए गए धान को खरीदी केंद्रों में विक्रय कर सकते हैं, जिसे समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। धान विक्रय के बाद समर्थन मूल्य की राशि किसानों के खातों में शीघ्र भुगतान की जा रही है।

संक्षिप्त समाचार

जलसो गांव में देवता पूजन को लेकर खूनी विवाद, तलवार और पाइप से हमला कर तीन लोगों को किया घायल

घर में घुसकर की मारपीट, टीवी-फ्रिज सहित घरेलू सामानों में तोड़फोड़; तिल्दा नेवरा पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, दो विधि से संघर्षरत बालक अभिरक्षा में

तिल्दा नेवरा,29 नवंबर। थाना तिल्दा नेवरा क्षेत्र के ग्राम जलसो में देवता पूजन की बात को लेकर रिश्तेदारों के बीच हुआ विवाद हिंसक रूप ले बैठा। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने कथित तौर पर घर में जबरन प्रवेश कर तलवार और लोहे के पाइप से हमला कर तीन लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट की गई। इतना ही नहीं, घर में रखे टीवी, फ्रिज सहित अन्य घरेलू सामानों में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। मामले में तिल्दा नेवरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं दो विधि से संघर्षरत बालकों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त तलवार, पाइप एवं अन्य सामग्री भी जब्त की है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी शनिराज गोड़ निवासी ग्राम जलसो ने थाना तिल्दा नेवरा में शिकायत दर्ज कराई कि 27 नवंबर 2026 को उनके रिश्तेदार शिव उईके, सुनीता उईके, सतीश उईके, शिवम उईके एवं अन्य लोगों के बीच घर में देवता पूजन की बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। इसी दौरान आरोपियों ने कथित तौर पर घर में जबरन प्रवेश कर प्रार्थी के साथ अश्लील गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और अपने पास रखे तलवार एवं पाइप से हमला कर दिया। हमले में प्रार्थी को गंभीर चोटें आईं। जब प्रार्थी की मां और भाई बीच-बचाव करने पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया गया। आरोपियों ने घर में रखे टीवी, फ्रिज एवं अन्य घरेलू सामानों को भी तोड़कर नुकसान पहुंचाया।

घटना की रिपोर्ट पर थाना तिल्दा नेवरा में अपराध क्रमांक 530/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 115(2), 351(2), 333, 324(4), 109(1), 3(5) बीएनएस तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) रायपुर श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमती चंचल तिवारी एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (विधानसभा) श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी ने तिल्दा नेवरा पुलिस को आरोपियों की शीघ्र पतासाजी कर गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तिल्दा नेवरा पुलिस ने



त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के कुछ ही घंटों के भीतर आरोपियों की पतासाजी कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही दो विधि से संघर्षरत बालकों को भी अभिरक्षा में लिया गया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई तलवार, पाइप एवं अन्य सामग्री जब्त की है। गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई पूरी कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वहीं दोनों विधि से संघर्षरत बालकों के संबंध में किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम

1. श्रीमती सुनीता उईके, पति शिवा उईके, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम जलसो, थाना तिल्दा नेवरा। 2. सतीश उईके, पिता नारद उईके, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम जलसो, थाना तिल्दा नेवरा।

इसके अतिरिक्त दो विधि से संघर्षरत बालकों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। ग्राम जलसो में पारिवारिक विवाद के दौरान हुई इस हिंसक घटना ने क्षेत्र में चर्चा का माहौल पैदा कर दिया है। मामूली पारिवारिक विवाद का इस तरह हिंसक रूप लेना चिंताजनक है। हालांकि, घटना के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी और हथियारों की जब्ती से कानून व्यवस्था के प्रति पुलिस की तत्परता सामने आई है। तिल्दा नेवरा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक और हिंसक गतिविधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

नारायणपुर में मदर मैरी की प्रतिमा को आग लगाने का प्रयास, अज्ञात लोगों पर एफआईआर

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बांग्लापारा स्थित एक चर्च के बाहर अज्ञात लोगों ने मदर मैरी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने और जलाने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज में आग की लपटें दिखने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। ईसाई समुदाय ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर क्रिसमस से पहले सुरक्षा कड़ी करने की मांग की है।

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में अज्ञात लोगों ने मदर मैरी की मूर्ति को जलाने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

जिले में अवैध धान पर प्रशासन की लगातार कार्रवाई, अबतक 32 प्रकरणों में 7,651 बोरी धान जब्त

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायगढ़, 29 नवम्बर.खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने तथा अवैध धान के भंडारण, परिवहन और अनियमित खरीदी-बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देशानुसार राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जांच कर रही हैं। इसी क्रम में 27 और 28 नवंबर को अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से भंडारित एवं परिवहन किए जा रहे धान को जब्त किया गया।

कापू में गोदाम से 70 बोरी धान जब्त–27 नवंबर को विकासखंड



धरमजयगढ़ के ग्राम पंचायत कापू में खाद्य एवं राजस्व विभाग के संयुक्त दल ने राजू निराला के गोदाम की जांच की। इस दौरान गोदाम में अवैध रूप से भंडारित 70 बोरी धान पाया गया, जिसका कुल वजन 28 क्विंटल है। संयुक्त दल द्वारा धान की जब्ती कर आवश्यक कार्रवाई की गई।

पटेलपाली में ट्रक से 550 बोरी धान पकड़ा गया–वहीं, 28 नवंबर को रायगढ़ तहसील के ग्राम पटेलपाली में ट्रक के माध्यम से धान का अवैध परिवहन किए जाने का मामला सामने आया। सूचना मिलने पर राजस्व एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान ट्रक में 550 बोरी धान का अवैध रूप से परिवहन किया जाना पाया गया। टीम द्वारा धान को जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की गई।

अब तक 32 प्रकरणों में 7,651 बोरी धान जब्त–जिले में अवैध धान के भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध 28 नवंबर 2026 तक कुल 32 प्रकरणों में 7,651 बोरी धान जब्त किया जा चुका है। 27 नवंबर तक जिले में 31 प्रकरणों में 7,101 बोरी धान जब्त किया गया था, जिसका कुल वजन 2,840.40 क्विंटल है। वहीं, 28 नवंबर को रायगढ़ तहसील के ग्राम पटेलपाली में ट्रक से 550 बोरी धान की अतिरिक्त जब्ती की गई। इसके साथ ही प्रकरणों की संख्या बढ़कर 32 और जब्त धान की मात्रा 7,651 बोरी हो गई है। जिला प्रशासन द्वारा धान खरीदी केंद्रों के साथ-साथ गोदामों एवं परिवहन मार्गों पर भी निगरानी रखी जा रही है। राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग के संयुक्त दलों द्वारा लगातार जांच की जा रही है, ताकि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध धान के भंडारण, परिवहन एवं खरीदी-बिक्री के मामलों में आगे भी जांच और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

स्व-सहायता समूहों को मिल रहे आजीविका के अवसर

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायगढ़, 29 नवम्बर. मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के नए अवसरों से जोड़कर उन्हें आर्थिक गतिविधियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। शासन की योजनाओं, प्रशिक्षण और आर्थिक सहयोग से महिलाएं अपनी पहचान बनाने के साथ परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। ऐसी ही प्रेरक कहानी रायगढ़ जिले के ग्राम धनागर की कमला चौधरी की है, जिन्होंने स्व-सहायता समूह से जुड़कर मशरूम उत्पादन को अपनी आजीविका का साधन बनाया है। आज वे न केवल इससे अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर रही हैं, बल्कि मास्टर ट्रेनर के रूप में दूसरी ग्रामीण



महिलाओं को भी मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं। कमला चौधरी रुक्मणी स्व-सहायता समूह से जुड़ीं और नियमित बैठकों में भाग लेकर बचत की शुरुआत की। समूह के माध्यम से उन्हें आजीविका के विभिन्न साधनों और शासन की योजनाओं की जानकारी मिली। आवश्यकता पड़ने पर समूह से कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा मिली। वहीं, अपनी बचत के आधार पर बैंक से भी ऋण प्राप्त हुआ। इस आर्थिक सहयोग ने उन्हें आजीविका के नए अवसर अपनाने और अपने कार्यों को आगे बढ़ाने का अवसर दिया।

मशरूम उत्पादन से मिली आय की नई राह–कमला ने बैंक से मिले ऋण का उपयोग खेती, पशुपालन और मशरूम उत्पादन जैसे आजीविका के कार्यों में किया। मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिलने के बाद उन्होंने ऑयस्टर तथा पैरा पुटू मशरूम का उत्पादन शुरू किया। लगातार मेहनत और अभ्यास से उन्होंने इस कार्य की तकनीक में दक्षता हासिल की। धीरे-धीरे मशरूम उत्पादन उनके लिए अतिरिक्त आमदनी का महत्वपूर्ण जरिया बन गया। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में भी मदद मिली।

शराब भट्ठी के पास चाकू लहराकर लोगों को धमका रहा बदमाश गिरफ्तार

राजनांदगांव, 29 नवंबर। चिखली शराब भट्ठी के पास चाकू लहराकर आने-जाने वाले लोगों को डराने-धमकाने वाले आदतन बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक बटनदार चाकू जब्त किया गया है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक सत्यप्रकाश तिवारी के पर्यवेक्षण में जिले में अवैध गतिविधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान 28 नवंबर को पुलिस को सूचना मिली कि चिखली शराब भट्ठी के पास एक व्यक्ति चाकू लहराकर लोगों को डरा-धमका रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी दीपक ठाकुर (25), निवासी स्टेशनपारा, बूढ़ी माई मंदिर के पास, वार्ड नंबर 12, चौकी चिखली को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक बटनदार चाकू बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 25 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ पूर्व में हत्या और आर्म्स एक्ट सहित अन्य मामले दर्ज हैं। कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई सहित प्रधान

एकलव्य विद्यालय छर्राटांगर में तीन दिवसीय 'उद्भव 2026' का भव्य शुभारंभ

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायगढ़, 29 नवम्बर.जनजातीय कला, संस्कृति, संगीत, नृत्य और साहित्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय छर्राटांगर घरघोड़ा में तीन दिवसीय संकुल स्तरीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक उत्सव 'उद्भव 2026' का भव्य शुभारंभ हुआ। 28 से 30 नवंबर तक आयोजित इस उत्सव में रायगढ़ संकुल के अंतर्गत आने वाले 8 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्सव की थीम 'विरासत, संस्कृति एवं राष्ट्रीय एकता' रखी गई है, जिसके माध्यम से जनजातीय परंपराओं, सांस्कृतिक विविधता और आपसी एकता का संदेश दिया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा सांसद श्री राधेश्याम राठिया उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में जनपद सदस्य श्रीमती अंबिका मुकेश राठिया,



सरपंच छर्राटांगर श्रीमती सुखमती राठिया, श्री घनश्याम राठिया सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना के साथ हुआ। इसके पश्चात राष्ट्रगान एवं विद्यार्थियों द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत एवं सम्मान किया गया। छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाते राज्यगीत 'अरपा पैरी के धार' की प्रस्तुति ने उपस्थित जनसमूह को भावविभोर कर दिया। उत्सव के पहले दिन विद्यार्थियों ने जनजातीय वाद्ययंत्रों पर आधारित सामूहिक संगीत की मनमोहक प्रस्तुति दी। पारंपरिक वाद्ययंत्रों की मधुर धुनों ने जनजातीय संगीत की समृद्ध परंपरा को जीवंत कर दिया। वहीं नाटक के माध्यम से विद्यार्थियों ने अपनी अभिनय प्रतिभा एवं रचनात्मकता का परिचय दिया। ऑर्केस्ट्रा की आकर्षक प्रस्तुति ने भी कार्यक्रम में संगीत और उत्साह का रंग भर दिया। उत्सव के आगामी दो दिनों में जूनियर एवं सीनियर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए समूह नृत्य, एकल नृत्य, गायन, वाद्य संगीत, चित्रकला, वाद-विवाद, भाषण, प्रश्नोत्तरी, नाटक, रचनात्मक लेखन और पारंपरिक कहानी वाचन जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थी अपनी कलात्मक, साहित्यिक एवं बौद्धिक प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों को एक-दूसरे की कला, संस्कृति और परंपराओं को जानने का अवसर मिलेगा।

अशोक देवांगन की मांग पर सड़क के लिए 3295.56 करोड़ रुपये स्वीकृत

राजनांदगांव।क्षेत्र के ग्रामीणों की बहुप्रतीक्षित मांग अब पूरी होने जा रही है। सुकुलदैहान से मोहारा मार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए राज्य शासन ने 32 करोड़ 95 लाख 56 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। पूर्व जिला पंचायत सभापति अशोक देवांगन के लगातार प्रयासों और जनप्रतिनिधियों के समक्ष इस सड़क की आवश्यकता को प्रमुखता से उठाने का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र के अनेक गांवों के ग्रामीणों को आवागमन की बेहतर और सुगम सुविधा मिलेगी।श्री देवांगन ने बताया कि सुकुलदैहान-मोहारा मार्ग की जर्जर स्थिति और आवागमन में होने वाली परेशानियों को देखते हुए क्षेत्र के ग्रामवासियों द्वारा लंबे समय से इस सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण की मांग की जा रही थी। ग्रामीणों की इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, लोक निर्माण विभाग मंत्री अरुण साव, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह एवं राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय को पत्र लिखकर सड़क निर्माण के लिए आवश्यक बजट उपलब्ध कराने तथा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया था। श्री देवांगन ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, लोक निर्माण विभाग मंत्री अरुण साव, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और सांसद संतोष पांडेय के विशेष प्रयासों एवं सहयोग से इस महत्वपूर्ण सड़क परियोजना को स्वीकृति मिल सकी है। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल राजनांदगांव जिले के सुकुलदैहान-मोहारा मार्ग, जिसकी कुल लंबाई 22.60 किलोमीटर है, के किलोमीटर 9/6 से 23/6 तक 14.20 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 3295.56 लाख रुपये अर्थात 32 करोड़ 95 लाख 56 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इस स्वीकृति के लिए वित्त विभाग की सहमति भी प्राप्त हो चुकी है। इस सड़क के निर्माण से कसारी, रुवांतला, सल्टीकरी, बसंतपुर, मोहारा सहित आसपास के अनेक गांवों के ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। वर्तमान में सड़क की स्थिति के कारण ग्रामीणों, किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और दैनिक आवागमन करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण होने से आवागमन अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और समय की बचत करने वाला होगा। इसके साथ ही क्षेत्र के किसानों को अपनी कृषि उपज बाजार एवं खरीदी केंद्रों तक पहुंचाने में भी सुविधा मिलेगी। श्री देवांगन ने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए बेहतर सड़क संपर्क सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। सड़क अच्छी होने से न केवल आवागमन सुगम होता है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार और रोजगार के अवसरों को भी गति मिलती है। सुकुलदैहान-मोहारा मार्ग का निर्माण क्षेत्र की वर्षों पुरानी आवश्यकता थी। ग्रामीणों की मांग को शासन और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रही है।

सूरज की रोशनी से रोशन हुआ घर, बिजली बिल हुआ शून्य

रायगढ़, 29 नवम्बर .कभी हर महीने बिजली बिल का इंतजार और उसके भुगतान की चिंता करने वाले धरमजयगढ़ निवासी यशवंत सिंह राठिया के घर में अब सूरज की रोशनी से बिजली तैयार हो रही है। घर की छत पर लगे सोलर पैनल ने उनकी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव लाया है, जिससे न केवल बिजली खर्च से राहत मिली है, बल्कि घरेलू बजट में भी हर महीने बचत होने लगी है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाकर यशवंत सिंह ने सौर ऊर्जा को अपने घर की जरूरत बनाया है। पिछले आठ महीनों से उन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है और उनका बिजली बिल शून्य हो गया है। यशवंत सिंह राठिया के लिए हर महीने बिजली बिल का भुगतान करना घरेलू खर्च का हिस्सा था। परिवार की अन्य जरूरतों के बीच बिजली बिल के लिए भी नियमित रूप से राशि निकालनी पड़ती थी। इसी दौरान उन्हें प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी मिली। उन्हें पता चला कि घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर सूर्य की ऊर्जा से बिजली का उत्पादन किया जा सकता है और बिजली खर्च में राहत पाई जा सकती है। योजना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने इसका लाभ लेने का निर्णय लिया और अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा लिया। इसके बाद उनके घर में सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन शुरू हो गया। देखते ही देखते हर महीने आने वाला बिजली बिल शून्य हो गया। जो राशि पहले बिजली बिल चुकाने में खर्च होती थी, अब वह परिवार की दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करने में काम आ रही है।

हर महीने 800 से 1000 रुपये की बचत

यशवंत सिंह बताते हैं कि सोलर पैनल लगने से पहले उन्हें हर महीने 800 से 1000 रुपये तक बिजली बिल देना पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलने के बाद पिछले आठ महीनों से उन्हें बिजली बिल का भुगतान नहीं करना पड़ रहा है। इससे परिवार को नियमित आर्थिक राहत मिल रही है। उनके अनुसार, योजना ने बिजली खर्च कम करने के साथ ही सौर ऊर्जा के महत्व को समझने का अवसर भी दिया है।

खुद लाभ लिया, अब दूसरों को भी दिखा रहे राह

योजना का लाभ मिलने के बाद यशवंत सिंह अब केवल अपने घर तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों और पड़ोसियों को भी सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वे लोगों को अपने अनुभव बताते हुए समझाते हैं कि घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर बिजली खर्च को कम किया जा सकता है। उनके घर में आया बदलाव आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आम परिवारों के लिए बिजली खर्च में राहत देने के साथ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने का भी माध्यम बन रही है।

अवैध धान के भंडारण एवं परिवहन पर जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

राजनांदगांव 29 नवम्बर। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान अवैध धान के भंडारण, परिवहन एवं उपार्जन केन्द्रों में अवैध धान खपाने के प्रयासों पर रोक लगाने के लिए लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध धान के कारोबार में संलिप्त कोचियों, बिचौलियों एवं उन्हें सहयोग करने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में आज छुरिया स्थित एक राईस मिल को सील करने की कार्रवाई की गई। साथ ही जिले में अवैध धान के 4 प्रकरण दर्ज कर कुल 674 कट्टा (284.40 क्विंटल) धान एवं एक वाहन जब्त किया गया।राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा छुरिया स्थित मेसर्स एआर राईस इंडस्ट्री के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर राईस मिल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान राईस मिल बंद पाई गई। मिल संचालक को जांच कराने के निर्देश दिए जाने के बावजूद उनके द्वारा जांच में आवश्यक सहयोग नहीं किया गया। जांच दल द्वारा अनियमितता की आशंका के मद्देनजर आगामी आदेश पर्यन्त राईस मिल को सील कर दिया गया है। मिल संचालक द्वारा नियमानुसार जांच कराए जाने के पश्चात ही राईस मिल खोलने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि उक्त राईस मिल के विरूद्ध गत वर्ष भी कोचियों एवं बिचौलियों को अवैध रूप से धान विक्रय करने संबंधी मामले में कार्रवाई की गई थी। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में



राईस मिल द्वारा धान उपार्जन केन्द्रों से 27 हजार 906.57 क्विंटल धान का उठाव किया गया था। जिसके विरूद्ध 18 हजार 772.07 क्विंटल चावल जमा किया जाना था। मिल द्वारा अब तक केवल 6 हजार 691.80 क्विंटल चावल जमा किया गया है तथा 12 हजार 80.27 क्विंटल चावल जमा करना शेष है। निर्धारित समय पर शेष चावल जमा नहीं किए जाने से कस्टम मिलिंग कार्य के प्रति मिल संचालक की उदासीनता भी सामने आई है। अन्य राज्यों से जिले में अवैध धान के प्रवेश को रोकने के लिए अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थापित जांच नाकों में सघन जांच की जा रही है। डोंगरगढ़ के बोरतलाव जांच नाका में जांच के दौरान महाराष्ट्र से अवैध रूप से धान का परिवहन करते पाए जाने पर एक वाहन सहित 420 कट्टा (183.40 क्विंटल) धान जप्त किया गया। इसी तरह मंडी डोंगरगढ़ द्वारा लालबहादुर नगर में 38 कट्टा (15 क्विंटल) तथा मंडी राजनांदगांव द्वारा मलपुरी राजनांदगांव स्थित एक पोहा मिल से 216 कट्टा (86 क्विंटल) धान जप्त किया गया। लाइसेंस की निर्धारित सीमा से अधिक धान का संग्रहण करने एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण जब्ती की कार्रवाई की गई। जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में अब तक अवैध धान के 42 प्रकरण दर्ज कर कुल 8 हजार 539 कट्टा (3 हजार 639.70 क्विंटल) धान एवं 6 वाहन जप्त किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा अवैध धान के भंडारण, परिवहन एवं विक्रय में संलिप्त व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विरूद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए सभी संबंधित विभागों द्वारा निरंतर निगरानी की जा रही है।

एक नजर

पत्रकारों के प्रति आत्मीयता और संवेदनशीलता की मिसाल बनीं ज्योति चंद्राकर

कुरूद 29 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। आपसी आत्मीयता, मेल-मिलाप और सुख-दुख की साझेदारी सामाजिक रिश्तों की असली पहचान है। इसी भावना के साथ नगर पालिका कुरूद की अध्यक्ष श्रीमती ज्योति भानु चंद्राकर ने गुरुवार को अपने गृह निवास पर 26 नवंबर को पत्रकारों के लिए शीतकालीन पारंपरिक व्यंजनों के साथ स्नेह मिलन कार्यक्रम रखा था। इस दौरान पत्रकारों के साथ आत्मीय चर्चा और विचारों का आदान-प्रदान होना था। लेकिन प्रखर समाचार के ब्यूरो प्रमुख, धनसिंह सेन की सुपुत्री श्रीमती वर्षा श्रीवास के आकस्मिक निधन का दुखद समाचार मिलते ही उन्होंने कार्यक्रम स्थगित करने का निर्णय लिया। उनका यह कदम बताता है कि उनके लिए औपचारिक आयोजनों से कहीं बढ़कर मानवीय संवेदनाएं और दूसरों के दुख में सहभागी होना है। दूसरों के दुख को अपना समझकर उत्सव स्थगित करना ही सच्चे सामाजिक संस्कार और बड़प्पन की पहचान है। ज्योति भानू चंद्राकर का यह निर्णय उनकी संवेदनशीलता और पत्रकारों के प्रति आत्मीय सम्मान को दर्शाता है।



तीन सरपंचों ने कहा-कोंटा विधायक कवासी लखमा दो सालों से लापता

सुकमा 29 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। जिले के कोंटा विधानसभा सीट से विधायक कवासी लखमा के क्षेत्र में गैरहाजिर रहने को लेकर तीन सरपंचों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्राम पंचायत गोंडपल्ली, गोंडेरास और अपड्डी के सरपंचों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विधायक की क्षेत्र में मौजूदगी और ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर चिंता जताई है। कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में सरपंचों ने दावा किया है कि कवासी लखमा लगभग दो वर्षों से क्षेत्रीय दौरा और सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर नहीं आए हैं। जिसमें आम जनता को अपनी समस्याओं को अवगत कराने में कठिनाई हो रही है। कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में सरपंचों ने लिखा है कि कोंटा विधायक कवासी लखमा कोंटा विधानसभा क्षेत्र से दो सालों से लापता हैं। हमारे क्षेत्र में क्षेत्र सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं वन अधिकारी से संबंधित अनेक जनसमस्याएं लंबित हैं। जिनके निराकरण के लिए आज जनता को विधायक की आवश्यता है। जनता में यह जिज्ञासा एवं चिंता है कि कोंटा विधायक गुमशुदा होने के संबंध में आज तक जनता को शासन-प्रशासन ने जानकारी नहीं दी है कि कोंटा विधायक कहां हैं? सरपंचों ने कलेक्टर से निवेदन किया है कि हमारे विधायक को खोजकर तत्काल जानकारी देने की कृपा करें। उल्लेखनिय है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा को आरोपी बनाया है। इस मामले में कवासी लखमा जेल में भी थे। सुप्रीम कोर्ट ने 03 फरवरी 2026 को कवासी लखमा को शराब घोटाले से जुड़े ईओडब्लयू-एसीबी और ईडी के दोनों मामलों में अंतरिम जमानत दी थी।

पीएम फसल बीमा फर्जीवाड़ा मामले में कृषि विस्तार अधिकारी सहित दो गिरफ्तार, एक फरार

जगदलपुर, 28 नवंबर। जिले के बुरगुम थाना पुलिस ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर कर बीमा राशि का लाभ लेने के मामले में हितग्राही किसानों की शिकायत के जांच के बाद ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मुन्ना लाल बघेल सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बुरगुम पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ग्राम जामगांव के किसानों के फर्जी हस्ताक्षर कर बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा राशि प्राप्त कर आरोपियों ने किसानों व बीमा कंपनी के साथ धोखाधड़ी की। अब तक की जांच में इस मामले में तीन आरोपियों की संलिप्तता पाई गई है, जिसमें से कृषि विस्तार अधिकारी मुन्ना लाल बघेल एवं अनिल सेठिया को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

फर्जी बिल से सरकारी राशि के भुगतान का मामला: वन मंडल पर जांच को भटकाने का आरोप, पुलिस जांच से न्याय की आस

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

छुरा 29 नवंबर। गरियाबंद वन मंडल के अंतर्गत वन परिक्षेत्र गरियाबंद में राज्य कैंपा मद से कराए गए आंवला वन (केशोडार) वृक्षारोपण कार्य में गोबर खाद खरीदी के नाम पर कथित फर्जी बिल के माध्यम से शासकीय राशि के भुगतान का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बारुका वन प्रबंधन समिति के नाम से बिल क्रमांक 06, दिनांक 31 मई 2022 के जरिए 28.80 घनमीटर गोबर खाद के एवज में 23,040 रुपये का भुगतान दर्शाया गया है, लेकिन समिति का दावा है कि उसके बैंक खाते में आज तक यह राशि प्राप्त नहीं हुई। मामले में वन परिक्षेत्र अधिकारी सहित अन्य जिम्मेदार वन अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।

शिकायतकर्ता नरेंद्र तिवारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, ए.पी.ओ. वर्ष 2018-19 एवं वृक्षारोपण



वर्ष 2022-23 के अंतर्गत आंवला वन (केशोडार) कार्य स्वीकृत किया गया था। इस कार्य में पौधों के उपयोग के लिए गोबर खाद क्रय का प्रावधान था। विभागीय अभिलेखों में बारुका वन प्रबंधन समिति के नाम से बिल प्रस्तुत कर भुगतान किए जाने का उल्लेख है। प्रमाणक वाउचर में राशि समिति के बैंक खाते में जमा किए जाने का भी उल्लेख किया गया है।

लेकिन समिति के खाते में राशि नहीं पहुंचने का दावा इस भुगतान प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है। शिकायतकर्ता के अनुसार, बारुका वन प्रबंधन समिति के गठन से लेकर आज तक समिति ने न तो गोबर खाद का संग्रहण किया है और न ही वन विभाग अथवा किसी अन्य संस्था को गोबर खाद का विक्रय या परिवहन किया है। समिति के पास अपनी कोई बिल बुक भी उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई है।

ऐसे में सवाल है कि समिति के नाम से बिल किसने तैयार किया? बिल में किस व्यक्ति या संस्था का बैंक खाता नंबर दर्शाया गया? भुगतान की राशि आखिर किस खाते में पहुंची? शिकायतकर्ता ने बिल क्रमांक 001 से 05 तथा क्रमांक 06 के बाद जारी अन्य बिलों की भी जांच कराने की मांग की है। आशंका जताई गई है कि समिति के नाम से कथित फर्जी बिलों का उपयोग अन्य शासकीय कार्यों में भी किया गया हो सकता है।

मामले में उप वन मंडलाधिकारी गरियाबंद की भूमिका भी जांच के दायरे में है। जब समिति से गोबर खाद क्रय किए जाने का ही खंडन किया जा रहा है, तो संबंधित कार्य का सत्यापन किस आधार पर किया गया? शिकायतकर्ता ने भुगतान प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और सत्यापन करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग की है। इसके साथ ही ऑक्सीजोन के नाम पर किए गए व्यय के बिल, वाउचर और कैशबुक की भी गहन जांच कराने की मांग उठाई गई है।

इस पूरे मामले में अब वन मंडल गरियाबंद की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता नरेंद्र तिवारी का आरोप है कि वन मंडल द्वारा पुलिस जांच को प्रभावित करने अथवा मामले को टालने के लिए विभागीय जांच लंबित होने का हवाला दिया जा रहा है। जबकि शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने स्वयं डीएफओ मयंक पाण्डेय को व्हाट्सएप और ई-मेल के माध्यम से दो-दो बार लिखित रूप से सूचित किया था कि इस प्रकरण में विभागीय जांच नहीं कराई जाए और पुलिस जांच के माध्यम से निष्पक्ष कार्रवाई की जाए।

शिकायतकर्ता के अनुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा संबंधित वन अधिकारी को कथन दर्ज कराने एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सूचना दिए जाने के बावजूद अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। विभागीय जांच का हवाला देकर पुलिस जांच में सहयोग नहीं किए जाने से मामले की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं।

शिकायतकर्ता नरेंद्र तिवारी ने विभागीय जांच के बजाय पुलिस की निष्पक्ष जांच पर विश्वास जताते हुए पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ से भी मामले में हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया है।

> जांच चल रहा है, दस्तावेज देखने से पता चलेगा। पुष्पेन्द्र साहू, तत्कालीन वन परिक्षेत्र अधिकारी (एसडीओ अंरण्य भवन)

हांदावाड़ा में जनचौपाल लगाकर प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

■ **नक्सलमुक्त होने के बाद पहली बार पहुंचे मंत्री केदार कश्यप और विधायक चैतराम अटामी, 10.28 करोड़ की लागत से तरमीगुंडा से हांदावाड़ा तक बनने वाली 7.40 किमी सड़क का किया भूमि-पूजन**



गीदम 29 नवंबर । अबूझमाड़ के दुर्गम वनांचल क्षेत्र हांदावाड़ा में जनचौपाल एवं दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के प्रभारी मंत्री एवं वन मंत्री केदार कश्यप शामिल हुए। नक्सलमुक्त होने के बाद पहली बार हांदावाड़ा पहुंचे मंत्री केदार कश्यप का ग्रामीणों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। इस दौरान दंतेवाड़ा विधायक चैतराम अटामी भी पहली बार हांदावाड़ा पहुंचे।

जनचौपाल में मंत्री केदार कश्यप ने ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं, आवश्यकताएं और विकास संबंधी मांगें सुनीं। ग्रामीणों को सीधे मंत्री के समक्ष अपनी बात रखने का अवसर मिला। विधायक चैतराम अटामी ने भी ग्रामीणों से संवाद कर क्षेत्र के विकास एवं जनकल्याण से जुड़े मुद्दों पर अपनी प्रतिबद्धता जताई।

10.28 करोड़ की लागत से बनेगी 7.40 किमी सड़क : कार्यक्रम के दौरान ग्राम तरमीगुंडा से हांदावाड़ा तक 7.40 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण कार्य का भूमि-पूजन किया गया। इस सड़क का निर्माण 10.28 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। सड़क बनने से क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, कृषि एवं अन्य आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुंच आसान होगी। इसके अलावा हांदावाड़ा क्षेत्र के लिए लगभग 1.57 करोड़ रुपये के अन्य विकास कार्यों की भी सौगात दी गई।

नक्सलमुक्त क्षेत्र में विकास कार्यों को मिलेगी गति : लंबे समय तक नक्सलवाद के प्रभाव और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित रहे अबूझमाड़ क्षेत्र में शांति स्थापित होने के बाद विकास कार्यों और प्रशासनिक पहुंच को लेकर नई संभावनाएं बन रही हैं। हांदावाड़ा में आयोजित जनचौपाल को शासन और ग्रामीणों के बीच सीधे संवाद के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। दीपावली मिलन समारोह के माध्यम से सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे का संदेश भी दिया गया।

जनप्रतिनिधि एवं भाजपा पदाधिकारी रहे उपस्थित : कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन, प्रदेश प्रवक्ता टेकेश्वर जैन, जिला प्रभारी शिवनारायण पाण्डेय, भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष गुप्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष अभिमन्यु सोनी, नवीन विश्वकर्मा, जिला उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा, जिला महामंत्री सत्यजीत चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष नन्दलाल मुड़ामी, दीपक बाजपेयी, जिला सह मीडिया प्रभारी राजेश बोरबेन, दंतेवाड़ा मंडल अध्यक्ष जय भंसाली, सुधराम भास्कर, युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री कुणाल ठाकुर, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राहुल असरानी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अरविन्द कुंजाम, अजजा मोर्चा प्रदेश मंत्री रामू नेताम, बारसूर मंडल अध्यक्ष बैसूराम मंडावी, मंडल महामंत्री राजेश नाग एवं संध्या शुक्ला, जिला पंचायत सदस्य ममता मंडावी, जगत पुजारी, सरपंच बृजेश कड़ती, कमला, विनय नाग, पायल गुप्ता, सुनीता भास्कर एवं अंती वेक सहित भाजपा के वरिष्ठ-कनिष्ठ कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में सड़क निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों के माध्यम से अबूझमाड़ के दुर्गम गांवों को मुख्यधारा से जोड़ने और क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का संदेश दिया गया।

मनिहारी का ठेला चलाने वाले की जीवनभर की जमापूंजी ले गए चोर



■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

कुरूद 29 नवंबर। थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मरौद में दिनदहाड़े हुई चोरी की सनसनीखेज वारदात ने ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान का ताला तोड़कर 50 हजार रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवरात सहित करीब 5 लाख रुपये की संपत्ति पार कर दी। सबसे पीड़ादायक पहलू यह है कि पीड़ित परिवार का मुखिया गांव-गांव घूमकर मनिहारी का ठेला चलाता है और बच्चों के भविष्य के लिए पाई-पाई जोड़कर यह पूंजी जुटाई थी। वारदात के बाद से पूरा परिवार गहरे सदमे में है।

ग्राम मरौद निवासी सतीश कुमार साहू (पिता मुनुलाल साहू) अपने पांच सदस्यीय परिवार के साथ रहते हैं। वे गांव-गांव घूमकर फैंसी और मनिहारी का ठेला लगाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उनकी बड़ी बेटी कॉलेज, छोटी बेटी हाईस्कूल और बेटा भी अध्ययनरत है। बच्चों की उच्च शिक्षा और भविष्य की सुरक्षा के लिए सतीश ने अपनी छोटी-सी आमदनी से धीरे-धीरे जेवर और नकदी जमा की थी। घटना के समय घर सूना था, जिसका फायदा उठाकर चोर अंदर घुसे और दो जोड़ी सोने के झुमके, पांच नग निकलेस पत्ती, तीन जोड़ी चांदी की पायल, एक करधन तथा 50 हजार रुपये नकद समेटकर फरार हो गए।

इस घटना में चोरी से ज्यादा चर्चा कुरूद पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली को लेकर हो रही है। परिजनों के अनुसार, वारदात की सूचना दोपहर 3:15 बजे ही थाने को दे दी गई थी, लेकिन पुलिस घंटे भर की देरी से मौके पर पहुंची। हैरानी की बात यह है कि कुरूद थाने से ग्राम मरौद की दूरी महज 9 किलोमीटर है। इतनी कम दूरी तय करने में इतना लंबा वक्त लगने से ग्रामीणों और पीड़ित परिवार में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि यदि पुलिस सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करती, तो घेराबंदी कर चोरों का सुराग लगाया जा सकता था।

दिनदहाड़े हुई इस वारदात से मरौद सहित आसपास के ग्रामीणों में भय का माहौल है। जीवनभर की मेहनत की कमाई लुट जाने से घर की महिलाओं का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए चोरों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और पीड़ित परिवार की जमापूंजी बरामद कर उन्हें न्याय दिलाया जाए।

स्वास्थ्य स्क्रीनिंग शिविर में गैर-संचारी रोगों के प्रति लोगों को किया जागरूक

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

धमतरी 29 नवंबर। जिला धमतरी के अंतर्गत सिविल अस्पताल कुरुद में जिला स्वास्थ्य विभाग, धमतरी द्वारा यूनिसेफ छत्तीसगढ़ एवं MCCR ट्रस्ट के सहयोग से गैर-संचारी रोगों पर विशेष स्वास्थ्य स्क्रीनिंग एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समुदाय स्तर पर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की शीघ्र पहचान, समय पर जांच एवं रेफ्रल को बढ़ावा देना तथा लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। शिविर के दौरान 236 बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई,जिसमें 31 बच्चों का सिकल सेल पॉजिटिव AS (वाहक) पाए गए जिनका अन्य लैब जांच करवाया गया। प्रतिभागियों को चिकित्सकीय परामर्श, प्रारंभिक जांच, स्वास्थ्य शिक्षा तथा आवश्यकता अनुसार रेफ्रल सेवाएं प्रदान की गईं। शिविर में विशेष रूप से सिकल सेल रोग, बाल मधुमेह जन्मजात हृदय रोग,



मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पूर्ण टीकाकरण तथा नियमित स्वास्थ्य जांच के महत्व पर समुदाय को जागरूक किया गया।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा बच्चों में मधुमेह के शुरुआती लक्षणों–जैसे अत्यधिक प्यास लगना, बार-बार पेशाब आना, अचानक वजन कम होना एवं अत्यधिक कमजोरी–की जानकारी साझा की गई तथा ऐसे लक्षण दिखाई देने पर तत्काल स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह दी गई। साथ ही सिकल सेल रोग की समय पर स्क्रीनिंग, नियमित उपचार एवं निरंतर परामर्श के महत्व को भी सरल एवं व्यवहारिक भाषा में समझाया गया।

कार्यक्रम में मितानिनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, महिला समूहों एवं समुदाय के सदस्यों की सक्रिय सहभागिता रही। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार के शिविर समुदाय तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने, गंभीर बीमारियों की प्रारंभिक पहचान सुनिश्चित करने तथा समय पर उपचार से जटिलताओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

शिविर के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि नियमित स्वास्थ्य जांच, समय पर रेफ्रल और परिवार स्तर पर जागरूकता बच्चों, महिलाओं एवं कमजोर वर्गों में गंभीर बीमारियों की रोकथाम और बेहतर प्रबंधन के लिए अत्यंत आवश्यक है।

इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में जिला स्वास्थ्य विभाग से डॉ. ए के टोन्डर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धमतरी के मार्गदर्शन में तथा डॉ प्रिय कंवर, जिला कार्यक्रम प्रबंधक,जिला NCD सलाहकार, विकासखंड स्तर से डॉ हेमराज देवांगन,खंड चिकित्सा अधिकारी,कुरुद, रोहित पांडेय, विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक एवं चिरायु टीम से डॉ सुशांत जांगड़े डॉ मंजुषा शर्मा डॉ पूजा उपाध्याय एवं समस्त टीम,NCD टीम,समस्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं मितानिनों का विशेष सहयोग रहा।

कृषि महाविद्यालय रायपुर में उत्साह से मनाया गया भारतीय संविधान दिवस



रायपुर 29 नवंबर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के कृषि महाविद्यालय में दिनांक 26 नवंबर 2026 को भारतीय संविधान दिवस उत्साह, गरिमा एवं राष्ट्रभावना के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कृषि महाविद्यालय, रायपुर की अधिष्ठाता डॉ. आरती गुहे एवं विशिष्ट अतिथि विश्वविद्यालय की एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक डॉ. सुबूही निषाद उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में डॉ. जी.पी. बंजारा, डॉ. अंबिका टंडन, डॉ. डी.के. चंद्राकर, डॉ. रामा मोहन साहू तथा एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी (छात्रा इकाई) डॉ. पायल जायसवाल सहित महाविद्यालय के प्राध्यापकगण, विद्यार्थी एवं एनएसएस स्वयंसेवक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक वाचन एवं संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा की शपथ के साथ किया गया। इस अवसर पर भारतीय संविधान के महत्व, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। मुख्य अतिथि डॉ. आरती गुहे ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय संविधान देश की एकता, अखंडता, समानता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का आधार स्तंभ है। प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है कि वह संविधान में निहित आदर्शों एवं मूल्यों का सम्मान करते हुए अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का भी ईमानदारी से निर्वहन करे।

जन्मदिन के बहाने कुरूद कांग्रेस में शक्ति प्रदर्शन

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता



कुरूद 29 नवंबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अब लगभग दो वर्ष शेष हैं, लेकिन कुरूद कांग्रेस में गुटबाजी के संकेत अभी से दिखाई देने लगे हैं। हाल ही में ग्राम सिरीं में वरिष्ठ कांग्रेसी कर्मठ नेता सोहेंदर सिंह गुरुदत्ता का जन्मदिन बड़े उत्साह से मनाया गया। समारोह में कांग्रेस के अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी को राजनीतिक गलियारों में शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। वहीं भखारा निवासी वरिष्ठ एवं कर्मठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भरत नाहर की अपनी अलग राजनीतिक पहचान और कार्यकर्ता और जन आधार है। ऐसे में कुरूद विधानसभा के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों भखारा और सिरीं में वरिष्ठ नेताओं के इर्द-गिर्द सक्रियता कांग्रेस के अंदरूनी समीकरणों की ओर इशारा कर रही है। वहीं अनेक कांग्रेसियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कुरूद से होकर गुजरने पर बार-बार एक ही निजी संस्थान में स्वागत किए जाने को लेकर भी अनेक कांग्रेसियों में नाराजगी की चर्चा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कुरूद से होकर गुजरना होता है तो कांग्रेस कार्यालय, काली मंदिर, सांधा चौक ,और नगर प्रवेश द्वार जैसे अनेकों सार्वजनिक स्थानों पर भी स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है ताकि अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को जुड़ने का अवसर मिले। सूत्र बताते हैं

राजनीतिक जानकारों के अनुसार कुरूद विधानसभा में चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आपसी मतभेद दूर कर संगठन में एकजुटता बनाए रखने की है। ऐसे में सवाल उठता है कि जन्मदिन और स्वागत समारोहों के बहाने सामने आ रहे शक्ति प्रदर्शन महज संयोग हैं या कुरूद कांग्रेस में किसी नए राजनीतिक समीकरण की शुरुआत।

मितानिन दिवस समारोह में विधायक ने सेवा के लिए मितानिनों का किया सम्मान

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

छुरा 29 नवंबर। नगर के शीतला मंदिर प्रांगण में स्वस्थ पंचायत सम्मेलन और मितानिन दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक रोहित साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल चंद्राकर ने की। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश साहू,भाजपा जिला महामंत्री चंद्रशेखर साहू,आशीष शर्मा, जनपद अध्यक्ष मीरा ठाकुर,नगर पंचायत अध्यक्ष लुकेश्वरी निषाद,जिला पंचायत सभापति लेखराज ध्रुवा,जिला पंचायत सभापति शिवांगी चतुर्वेदी, छुरा भाजपा मंडल अध्यक्ष खोमन चंद्राकर , खड़सा भाजपा मंडल अध्यक्ष हेमंत सिन्हा,जनपद उपाध्यक्ष कुलेश्वर सोनवानी,जनपद सदस्य पंकज निर्मलकर,दुलारी



साहू ,सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। इस अवसर पर ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य जागरूकता, मातृ-शिशु देखभाल और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को घर-घर तक पहुँचाने में जुटी मितानिन बहनों को विधायक रोहित साहू द्वारा साड़ी भेंटकर सम्मानित किया गया। गांव-गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की पहली कड़ी के रूप में काम करने वाली मितानिनों के सेवा कार्यों को रेखांकित करते हुए उन्हें साड़ी भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। सम्मेलन के माध्यम से ग्राम पंचायतों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के मानकों पर सशक्त बनाने तथा आमजनों को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक रोहित साहू ने कहा कि मितानिन बहनें ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूत आधारशिला हैं। धूप, बारिश या किसी भी मौसम की परवाह किए बिना वे गांव के अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सेवाएं और जागरूकता पहुँचाती हैं। जब हर पंचायत स्वस्थ और जागरूक होगी, तभी क्षेत्र और प्रदेश का समग्र विकास संभव है। मितानिन बहनों का यह सम्मान उनके त्याग, परिश्रम और सेवा भाव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का माध्यम है।भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल चंद्राकर का ने कहा कि सेवा और समर्पण की जीवंत मिसाल हमारी मितानिन बहनें समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं। कठिन परिस्थितियों और संकट के समय में भी उन्होंने जिस निष्ठा से लोगों की सेवा की है, वह सराहनीय है। स्वस्थ पंचायत की परिकल्पना तभी साकार हो सकती है जब जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य अमला और ग्रामवासी मिलकर काम करें। आज का यह सम्मान समारोह सेवाभाव से जुड़े हर कार्यकर्ता और मितानिन बहन के मनोबल को और ऊँचा करेगा। कार्यक्रम को जिला पंचायत सभापति लेखराज ध्रुवा, शिवांगी चतुर्वेदी, जनपद अध्यक्ष मीरा ठाकुर और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया।

न्यायालय नायब तहसीलदार डोंगरगढ़, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 20260909230027-अ/6 (अ)-वर्ष 2025-26

एतद सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, आवेदक दुकालु राम भारती आ. मेहतरू भारती जाति सतनामी निवासी मोहरा तहसील डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव द्वारा आवेदन पेश किया है कि आवेदक के नाम पर ग्राम मोहरा पटवारी हल्का नं. 05 में स्थित कृषि भूमि आन लाईन अभिलेख में खसरा नं. 183, 257/2 रकबा 0.210, 0.150 हेक्टेयर कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.360 हेक्टेयर भूमि दर्ज है। आवेदक के ज्ञान पुस्तिका में खसरा नं. 183, 331/1,257/2 रकबा 0.210, 0.242, 0.150 हेक्टेयर कुल खसरा 03 कुल रकबा 0.602 हे. भूमि दर्ज है। आन लाईन अभिलेख में खसरा नं. 331/1 रकबा 0.242 हेक्टेयर में दर्ज नही है। जिसके कारण आवेदक को कृषि कार्य करने में परेशानी से रही है। आवेदक द्वारा आन लाईन रिकार्ड किये जाने बाबत् आवेदन पत्र, बी-1, आधार कार्ड की छायाप्रति पेश किया है।

अतः उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को उजर व आपत्ति हो वे यह दिनांक 30.11.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकते है। नियत समयावधि में आपत्ति प्राप्त नही होने के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 23.10.2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

मुहर

नायब तहसीलदार
डोंगरगढ़

गुल से लिपटी तितली को गिरा कर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा..



छत्तीसगढ़ की पहचान सिर्फ घने जंगल, वन्य जीव और आदिवासी संस्कृति से नहीं होगी। जंगलों के बीच रंग-बिरंगे पंखों के साथ उड़ती तितलियां भी प्रदेश की जैव विविधता की नई पहचान बन रही हैं। 201 प्रजातियों की तितलियों का दस्तावेजी करण हो चुका है। इनमें 19 प्रजातियां ऐसी हैं, जो प्रदेश में पहली बार दर्ज की गई। 2019 से 2024 तक सभी 33 जिलों में हुए सर्वे के बाद सामने आई इस तस्वीर ने छ.ग. के जंगलों में छिपी तितलियों की दुनिया को सामने ला दिया है। अब राज्य पहली राजकीय तितली चुनने की तैयारी में है। वन, जलवायु परिवर्तन विभाग ने 3 प्रजातियों को अंतिम सूची में रखा है।

इनमें कॉमन बैंडेड पीकॉक, ऑरेंज ओकलीफऔर स्पॉट स्वॉर्डटेल शामिल हैं। चयन में इनकी उप लब्धता, पारिस्थितिक महत्व, संरक्षण मूल्य, विशिष्ट पहचान और लोगों के आकर्षण को आधार बनाया जाएगा। बस्तर की बात करें तो यहां की तस्वीर और भी दिलचस्प है। कांगेरघाटी राष्ट्रीय उद्यान में 252 से अधिक तितली प्रजातियों की मौजूदगी दर्ज की गई है।जंगल, जल स्रोत, घासभूमि और अलग-अलग तरह की वनस्पतियां, तितलियों को अनुकूल वातावरण देती हैं। कांगेर घाटी के कुछ क्षेत्रों में एक ही स्थान पर 100 से अधिक प्रजातियां देखी जा सकती हैं। कॉमन जेम, ऑरेंज ओकलीफ, ब्लू टाइगर, प्लेन टाइगर, कॉमन मैप जैसी तितलियां आकर्षण का केंद्र हैं। अक्टूबर से फरवरी के बीच इनकी गतिविधियां खास तौर पर देखने मिलती हैं।

महज 249.72 पैसे में सीएम पद की कुर्सी गंवाने वाले राजनेता



राजनीति की किताब का यह दिलचस्प किस्सा कोई 5/6 दशक पुराना है। छग विधानसभा में पिछली बार के चुनावों में प्रत्याशियों द्वारा चुना खर्च की सीमा 40 लाख चुनाव आयोग ने तय की है। एक समय वह भी था जब चुनाव में महज ?250 से ज्यादा खर्च होना साबित हो गया तो कांग्रेस के कद्दावर नेता डीपी मिश्र को सीएम पद गंवाना पड़ा था। इंदिरा गांधी के सलाह कार और मप्र के सीएम रहे द्वारका प्रसाद मिश्र की गिनती कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में होती थी। डीपी मिश्र यानी द्वारका प्रसाद मिश्र मध्यप्रदेश की राजनीति का बड़ा नाम थे। वह मध्यप्रदेश के सीएम रहे लेकिन उन्हें एक ऐसे राजनेता के रूप में भी याद किया जाता है, जिन्होंने महज ?249.72 पैसे की वजह से सीएम पद गंवा दिया था। दरअसल 25 मार्च 1969 को मध्यप्रदेश के तब के सीएम नरेशचंद्र सिंह ने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद राजनीति के गलियारों में ये खबर फैल गई थी कि द्वारका प्रसाद मिश्र फिर से प्रदेश के सीएम बनने वाले हैं। क्यों कि कांग्रेस का पूरा कंट्रोल उस समय द्वारका प्रसाद मिश्र के हाथ में ही था। नरेशचंद्र सिंह मप्र के पहले, इक लौते आदिवासी सीएम थे, लेकिन वह सीएम पद पर केवल 13 दिनों तक ही रहे। 12 मार्च 1969 को तब सीएम गोविंद नारायण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था, इसके बाद 13 मार्च को नरेशचंद्र सिंह सीएम बने थे लेकिन 13 दिन बाद 25 मार्च को उन्हें पद छोड़ना पड़ा। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिससे मप्र की राजनीति का पूरा समीकरण ही बदल गया।कसडोल (छत्तीसगढ़) विस उपचुनाव में पराजित कमल नारायण शर्मा की याचिका पर फैसला आया और सिद्ध हो गया कि डीपी मिश्रा कसडोल के उपचुनाव में अनियमितताएं बरती गईं, नतीजा ये हुआ कि चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया। कसडोल के उपचुनाव में डीपी मिश्र के चुनाव एजेंट पं.श्यामाचरण शुक्ल थे, लेकिन जब डी पी मिश्र चुनाव जीत गए, उनकी टीम से चुनाव पर किये जाने वाले खर्चों के बिल कहीं खो गये। बाद में



कमल नारायण शर्मा ने जीत के खिलाफ याचिका दायर की। अस्ल में शर्मा को कहीं से ?6300 का एक बिल मिल गया, जिस पर डीपी मिश्र के चुनाव एजेंट पं.श्याम चरण शुक्ल के हस्ताक्षर थे। यहीं से चुनाव का पूरा गणित ही बदल गया। कहा ये भी जाता है एक बड़े कांग्रेसी ने डीपी मिश्र को धोखा दिया था अहम दस्तावेज कमल नारायण शर्मा को उपलब्ध करवाए थे। इसके बाद मई 1963 में कस डोल उपचुनाव निरस्त कर दिया गया, क्योंकि ये पाया गया कि डीपी मिश्र ने चुनाव में निर्धारित रकम से ?249.72 पैसे ज्यादा खर्च किए थे। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले के सामने आने के बाद डीपी मिश्र को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने अयोग्य घोषित कर दिया। कोर्ट के इस फैसले ने डीपी मिश्र के राजनीतिक जीवन को ही बदल कर रख दिया। हालांकि बाद में मिश्र, इंदिरा गांधी के सलाहकार रहे और बाद में राजीव गांधी के समय भी सक्रिय दिखे। आरोपों से बचने, डीपी मिश्र के बारे में एक बात और बहुत चर्चा में रही है कि वह जब मप्र के सीएम बने तो उनके बड़े बेटे ने भोपाल में अपनी चलती हुई दवाई की दुकान को बंद कर दिया। दुकान का नाम जानकी फार्मेसी था, भोपाल में हमीदिया अस्पताल के पास थी। इसके पीछे की वजह ये सुनने में आई, कोई मिश्रा पर ये आरोप ना लगा सके, जानकी फार्मेसी में हमीदिया अस्पताल की जरूरतें पूरी की जा रही हैं। पिता के लिए बेटे की कुर्बानी उस वक्त काफी चर्चा का विषय बनी थी क्योंकि दुकान काफी चलती थी और डीपी मिश्र के बेटे ने पिता की प्रतिष्ठा के लिए दुकान को बंद कर दिया था।

13 दिन में दो सीएम ने दिया था इस्तीफा

12 मार्च 1969 को मध्यप्रदेश के तब सीएम गोविंद नारायण सिंह ने इस्तीफा दे दिया, इसके बाद 13 मार्च को छग के



सारंगढ के राजा नरेशचंद्र सिंह बने। लेकिन उन्हें भी 13 दिन बाद यानी 25 मार्च को पद छोड़ना पड़ा। नरेशचंद्र सिंह मप्र के पहले और इकलौते आदिवासी सीएम थे। वे केवल 13 दिन सीएम रहे और 14 वें दिन उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और फिर एक तरीके से राजनीति से संन्यास ही ले लिया। छग बनने के बाद अजीत जोगी के जाति विवाद के बाद विष्णुदेव साय पहले आदिवासी सीएम बने हैं।

नवजात बच्चों को बेचने वाला गिरोह

रायपुर से देश के 8 राज्यों में 26



नवजात बच्चों को बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। गुढ़ियारी के दिवाकर अस्पताल को लीज पर लेकर अवैध कारोबार चलाया जा रहा था। यहां सिर्फ 3 डिलीवरी हुईं, लेकिन 26 बच्चों के फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र तैयार किए गए। गिरोह लड़कों को 12 लाख, लड़कियों को ?5 लाख में बेचता था। आजाद चौक पुलिस ने अस्पताल संचालक को गिरफ्तार कर एसआईटी जांच शुरू कर दी है, सिंडिकेट ने गुढ़ियारी के बंसत विहार स्थित दिवाकर अस्पताल को लीज पर लिया था। अस्पताल में 3 बच्चों की ही डिली वरी कराई गई थी।इसके बावजूद 26 बच्चों के फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र जारी किए गए। इन्हीं नकली दस्तावेजों के सहारे नवजातों को दूसरे राज्यों में बेचा जाता था। पुलिस ने अस्पताल के संचालक डॉ. खिरसिंधु महानंद को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में यह चौंकाने वाली बात सामने आई है कि बच्चे खरीदने वाले दंपती उनकी जाति और धर्म तक पूछते थे। गिरोह के बिचौलिए नि-संतान दंपतियों की जानकारी जुटा कर संपर्क करते थे। सौदे में लड़कियों की कीमत ?5 लाख तय थी। वहीं लड़कों को ?10 से 12 लाख तक में बेचा जाता था। कई महिलाओं ने आर्थिक तंगी के चलते खुद ही अपने बच्चे गिरोह को सौंपे थे। पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश आजाद चौक इलाके में हुआ। वहां सड़क पर दो महिलाओं के बीच पैसे के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद पुलिस ने जांच की तो पूरे सिंडिकेट की परतें खुलती चली गईं। आरोपियों के मोबाइल से नवजात बच्चों के वीडियो बरामद हुए हैं। रैकेट में डॉक्टर, दलाल, केयरटेकर, अकाउंटेंट और नर्स निगम कर्मियों की मिलीभगत सामने आ रही है !

और अब बस

» छत्तीसगढ़ के चर्चित डी ?म एफ घोटाले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

» 14 दिसंबर से चलेगा छग का विधानसभा का शीतकालीन सत्र, धान खरीदी और शिक्षकों की कमी पर सरकार को घेरेगा विपक्ष।

» राजिम में ?33 करोड़ के बने लक्ष्मण झूले की हालत खराब होने लगी है। पुल के लोहे में जंग लग रही है, चार साल में ही रंग-रोगन उखड़ने लगा है।

40 वार्डों में कांग्रेस की मजबूती का संकल्प

रायपुर 29 नवंबर। बिरगांव नगर निगम चुनाव की तैयारियों एवं संगठनात्मक रणनीति को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ग्रामीण एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बिरगांव के संयुक्त तत्वावधान में बंजारी मंदिर, रावाभाठा स्थित हॉल में विशाल कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में बिरगांव नगर निगम के सभी 40 वार्डों से हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं पार्षद पद के दावेदारों की उपस्थिति रही।

सम्मेलन में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने अपने संबोधन में केंद्र एवं राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों के कारण आम जनता महंगाई की मार झेलने को मजबूर है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य सामग्री सहित रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ने से आम परिवारों का बजट बिगड़ गया है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपैया जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। गरीब, मध्यमवर्गीय परिवार, किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी सभी बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। बिजली बिलों में बढ़ोतरी ने आम उपभोक्ताओं की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। भाजपा सरकार ने जनता से जो वादे किए थे, उनके क्रियान्वयन और जमीनी परिणामों पर जवाब देना चाहिए।

श्री बैज ने कहा कि महतारी वंदन योजना के नाम पर महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर महंगाई के कारण घरेलू खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। रसोई गैस, राशन, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के खर्च ने



परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है। केवल योजनाओं के प्रचार से जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होता, बल्कि सरकार को महंगाई पर नियंत्रण और आम लोगों को वास्तविक राहत देने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि वे जनता के बीच जाकर इन मुद्दों को मजबूती से उठाएं और भाजपा सरकार की नीतियों के संबंध में लोगों को जागरूक करें।

बिरगांव नगर निगम चुनाव के मुख्य पर्यवेक्षक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने कहा कि बिरगांव में कांग्रेस के महापौर के कार्यकाल में शहर को टैंकर मुक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक काम किया गया। जब कांग्रेस की महापौर ने जिम्मेदारी संभाली थी, उस समय बिरगांव के अलग-अलग वार्डों में लगभग 700 पानी के टैंकर पहुंचते थे। पेयजल की समस्या से जूझ रहे शहर को राहत दिलाने के लिए जल आवर्धन योजना को स्वीकृति दिलाई गई और इसके लिए 104 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई। इस योजना के माध्यम से बिरगांव को टैंकरों पर निर्भरता से मुक्त करने का काम किया गया। यह कांग्रेस की दूरदर्शी सोच और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम था। कांग्रेस सरकार के दौरान बिरगांव में शासकीय महाविद्यालय खोलने की पहल को भी प्राथमिकता दी गई। उन्होंने कहा कि आज भाजपा सरकार के कार्यकाल में बिरगांव की विकास योजनाएं ठप पड़ी हैं। स्थानीय समस्याओं, प्रदूषण और बुनियादी सुविधाओं को लेकर कांग्रेस जनता के बीच मजबूती से आवाज उठाएगी। उन्होंने सभी 40 वार्डों के कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव की तैयारी में जुटने और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। रायपुर ग्रामीण के पूर्व विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि बिरगांव में शासकीय महाविद्यालय खोलना यहां के युवाओं और विशेषकर छात्राओं को उच्च शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। इसके लिए उन्होंने विधायक रहते हुए लगातार प्रयास किए और क्षेत्र के विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय बिरगांव में विकास और जनसुविधाओं को प्राथमिकता दी गई, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद विकास कार्यों की गति थम गई है। क्षेत्रीय विधायक मोतीलाल साहू की निष्क्रियता के कारण बिरगांव के विकास से जुड़े अनेक मुद्दे लंबित हैं। उन्होंने कांग्रेसजनों से आपसी समन्वय और एकजुटता के साथ जनता के बीच पहुंचकर क्षेत्र की समस्याओं को उठाने तथा चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया।

जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ग्रामीण के जिलाध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे ने कहा कि सभी 40 वार्डों से हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति संगठन की सक्रियता, एकजुटता और चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के उत्साह का प्रमाण है। बिरगांव की जनता प्रदूषण, महंगाई, बढ़ते बिजली बिल और बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं से जूझ रही है। कांग्रेस की महापौर ने पानी की समस्या से शहर को राहत दिलाने के लिए ऐतिहासिक कार्य किया, वहीं कांग्रेस सरकार के समय जल आवर्धन योजना और शासकीय महाविद्यालय जैसी महत्वपूर्ण सौगातें बिरगांव को मिलीं। लेकिन भाजपा सरकार के आने के बाद विकास कार्यों पर विराम लग गया है। महापौर ने लगातार नगर निगम की बैठकों में विकास से जुड़े प्रस्ताव पारित कर राज्य शासन को भेजे, लेकिन भाजपा सरकार ने बिरगांव के साथ भेदभाव करते हुए आवश्यक सहयोग नहीं दिया।

भरत जैन क्षेत्रीय रेल्वे परामर्शदात्री समिति में शामिल

रायपुर 29 नवंबर। भरत जैन को क्षेत्रीय रेल्वे परामर्शदात्री समिति में बतौर सदस्य मनोनीत किया गया है। देश के सबसे बड़े व्यापारिक



संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के नेशनल वाइस चेयरमेन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य श्री अमर पारवानी, छत्तीसगढ़ इकाई के चेयरमेन श्री जितेन्द्र दोशी, श्री विक्रम सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष श्री परमानन्द जैन, वाइस चेयरमेन श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री जीवन बजाज, प्रदेश महामंत्री श्री अवनीत सिंह, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री विजय पटेल, कार्यकारी अध्यक्ष श्री राजेन्द्र जग्गी, श्री वासु माखीजा, श्री राम मंधान, श्री भरत जैन, श्री राकेश ओचवानी एवं श्री शंकर बजाज ने संयुक्त रूप से बताया कि श्री भरत जैन जी का यह मनोनयन उनकी वर्षों की निष्ठा, व्यापारियों के हितों के लिए निरंतर संघर्ष और समाज सेवा के प्रति समर्पण का परिणाम है।

पीएम मोदी ने युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने की प्रेरणा दी: बजाज



रायपुर 29 नवंबर। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 140 वे एपिसोड का प्रसारण अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ क्रमांक 130 पी जामगांव में सुना। तत्पश्चात अशोक बजाज ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात का प्रत्येक एपिसोड ज्ञान और प्रेरणा से परिपूर्ण होता है। इस संस्करण में उन्होंने नशापान की बुराइयों की जानकारी देते हुए देशवासियों विशेषकर युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने की प्रेरणा दी। श्री बजाज ने कहा कि नशे के खिलाफपीएम श्री मोदी का पहल स्वागत योग्य है, उनकी प्रेरणा से अब नशामुक्ति अभियान में तेजी आएगी। इस दौरान दयालूराम गाड़ा, दलजीत चावला, शांतनु सिन्हा, हेमन्त तारक, बूथ अध्यक्ष शेषनारायण सिन्हा, किशन सिन्हा, समारूराम साहू, तुलाराम साहू, रूपेंद्र चंद्राकर, पिकेश्वर सिन्हा, गंगू राम साहू एवं नारायण वैष्णव सहित काफी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

साइंस कॉलेज ग्राउंड में उमड़े उद्योग जगत के लोग

रायपुर 29 नवंबर। साइंस कॉलेज ग्राउंड, रायपुर में चल रहे 16वें राष्ट्रीय एक्सपो (स्टील एवं पावर) के दूसरे दिन आज औद्योगिक उत्साह चरम पर दिखाई दिया। इंदौर इन्फोलाइन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उरला इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन, रायपुर के विशेष सहयोग से आयोजित इस चार दिवसीय (27 से 30 नवम्बर 2026) भव्य औद्योगिक प्रदर्शनी में दूसरे दिन व्यापारिक आगंतुकों, इंजीनियरों, प्लांट हेड, प्रोक्योरमेंट अधिकारियों और उद्यमियों की भारी आवाजाही दर्ज की गई।



प्रदर्शनी के दूसरे दिन अधिकांश स्टॉलों पर मशीनों और उपकरणों का लाइव डेमोंस्ट्रेशन आगंतुकों के लिए मुख्य आकर्षण बना रहा। स्टील, पावर, सीमेंट, माइनिंग और हेवी इंजीनियरिंग क्षेत्रों से जुड़े उद्योग प्रतिनिधियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और ऊर्जा-कुशल समाधानों की कार्यप्रणाली को प्रत्यक्ष रूप से परखा। प्रदर्शकों के अनुसार, पहले दिन की तुलना में दूसरे दिन गंभीर व्यावसायिक पूछताछ (बिज़नेस इन्क्वारीज़) और तकनीकी चर्चाओं में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली।

एक्सपो के दूसरे दिन बी2बी बिजनेस मीटिंग्स और वेंडर डेवलपमेंट गतिविधियों ने जोर पकड़ा। बड़े औद्योगिक समूहों की क्रय (प्रोक्योरमेंट) टीमों ने स्थानीय व राष्ट्रीय स्तर के निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, डीलर्स, वितरकों, स्टॉकिस्ट्स और सिस्टम इंटीग्रेटर्स के साथ सीधे संवाद कर भविष्य की आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चैन) और नए करारों की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया। यह मंच क्षेत्रीय एमएसएमई इकाइयों को बड़े उद्योगों से जोड़ने में सेतु का कार्य कर रहा है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई मिनिस्ट्री) से अनुमोदित इस प्रदर्शनी में पीएमएस योजना के माध्यम से मिल रही वित्तीय सहायता का लाभ उठाते हुए बड़ी संख्या में सूक्ष्म, लघु उद्यम और स्टार्टअप्स अपनी नवाचारी तकनीकों का प्रदर्शन कर रहे हैं। रायपुर, भिलाई, बिलासपुर और दुर्ग के साथ-साथ मुंबई, नागपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता एवं हैदराबाद जैसे प्रमुख औद्योगिक केंद्रों से आए 100 से अधिक प्रदर्शक अपने 10,000 से अधिक औद्योगिक उत्पादों के साथ यहाँ मौजूद हैं।

प्रदर्शनी में रखे गए उत्पादों एवं मशीनरी का कुल अनुमानित मूल्य ?50 करोड़ से अधिक है, वहीं इस आयोजन के माध्यम से आगामी एक वर्ष में ?150 करोड़ से अधिक के व्यावसायिक सौदे और नए अवसर सृजित होने का अनुमान है। अपने पिछले 15 संस्करणों में 4,000 से अधिक प्रदर्शकों और 90,000 से अधिक व्यापारिक आगंतुकों का विश्वास जीत चुका यह एक्सपो मध्य भारत के औद्योगिक विकास को नई दिशा दे रहा है।

भाजपा ने ही ओबीसी समाज को दिया सर्वाधिक सम्मान : ललित

रायपुर 29 नवंबर। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नवनियुक्त राष्ट्रीय महामंत्री एवं विधायक ललित चन्द्राकर ने कहा है कि राजनीतिक दृष्टि से यदि किसी दल ने ओबीसी समाज को वास्तविक सम्मान दिया है, तो वह केवल भाजपा है। श्री चन्द्राकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए न केवल अलग मंत्रालय का गठन किया गया, बल्कि निरंतर जनकल्याणकारी योजनाएँ भी चलाई जा रही हैं। आज सांसद, विधायक और मंत्री से लेकर विभिन्न जनप्रतिनिधियों के रूप में ओबीसी वर्ग की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नवनियुक्त राष्ट्रीय महामंत्री श्री चन्द्राकर ने शनिवार को रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय (कुशाभाऊ ठाकरे परिसर) में आयोजित पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए श्री चन्द्राकर ने अपनी नई जिम्मेदारी के लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि एक सामान्य कार्यकर्ता को राष्ट्रीय महामंत्री जैसा महत्वपूर्ण दायित्व सौंपना सौभाग्य की बात है। यह सम्मान पूरे छत्तीसगढ़ और देश के हर उस कार्यकर्ता का सम्मान है जो निष्ठा से संगठन के लिए कार्य करता है। श्री चन्द्राकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि नेतृत्व ने जिस विश्वास और विचार के साथ उन्हे यह जिम्मेदारी दी है, वे उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ धरातल तक ले जाएंगे। श्री चन्द्राकर ने कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर की चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा में हर कार्यकर्ता योग्य है और पार्टी उसकी क्षमता के अनुरूप समय-समय पर दायित्व बदलती रहती है।



कौशल किशोर मिश्र प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी की ओर से तरुण छत्तीसगढ़, तरुण छत्तीसगढ़ प्रेस टॉवर, प्रेस काम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं प्रकाशित प्रधान संपादक- कौशल किशोर मिश्र, पंजी. क्रं. 45088/85 डाक पं.छ.ग./रायपुर संभाग/33/2024-26